● वर्ष-5
● अंक-266
रायपुर, बुधवार
24 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> खेलों के लिए बेहतर...

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2 नई योजनाओं को मंजूरी

साय कैबिनेट के बड़े फैसले

रायपुर। मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, सशक्तीकरण, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ''विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) = वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़'' के प्रारूप का अनुमोदन किया है। भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के अनुरूप लागू की जा रही इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिवस अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत संरचना निर्माण, आजीविकामूलक परिसंपत्तियों के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत आधारित समेकित विकास, विभागीय योजनाओं के अभिसरण तथा पीएम गति शक्ति से समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विकास कार्यों की बेहतर कार्ययोजना एवं निगरानी के

लिए आधुनिक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करते हुए पारदर्शिता, सुशासन एवं जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात 60=40 रहेगा तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य बजट में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2. मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ''अटल आजीविका समृद्धि हाट'' योजना प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प आदि), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी आदि), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र आदि), विपणन केंद्र तथा आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इस योजना का उद्देश्य उपलब्ध अधोसंरचना और मशीनरी का बेहतर उपयोग करते हुए स्थानीय उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इससे ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

अटल आजीविका समृद्धि हाट'' के माध्यम से कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, सेवा व्यवसाय, डिजिटल तकनीक, हरित ऊर्जा तथा ग्रामीण बाजारों को नई गति मिलेगी और प्रदेश की ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद ने आज छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। इस नीति से अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, जैव उर्वरक उत्पादन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना को मंजूरी

साय कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से फ्रअटल आजीविका समृद्धि हाटफ्र योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत सृजन केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, सेवा केंद्र, विपणन केंद्र और आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे. हथकरघा, हस्तशिल्प, डेयरी, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर और डिजिटल सेवाओं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा.

आतंकवाद से लेकर तकनीकों तक ब्रिक्स की अहम भूमिका: पीएम मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक खास संदेश साझा कर भारत के विजन को दुनिया के सामने रखा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए ब्रिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया। भारत अपनी अध्यक्षता में इन मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाएगा। पीएम मोदी के मुताबिक, इस कदम से वैश्विक स्तर पर सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी।

बैठक के दौरान भारत ने एक बार फिर विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने की प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता न केवल सदस्य देशों के हितों की रक्षा करेगी, बल्कि %ग्लोबल साउथ%की प्राथमिकताओं का भी पूरा समर्थन करेगी। भारत का उद्देश्य एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित और समावेशी दुनिया के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देना है। आज के दौर में सुरक्षा के आयाम बदल चुके हैं। अब पारंपरिक खतरों के साथ-साथ डिजिटल मोर्चे पर भी चुनौतियां बढ़ रही हैं।

एमएचए का नया एफसीआरए नियम लागू

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंड रूल्स, 2026 (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम) को संशोधित किया है। इसमें धार्मिक श्रेणी के तहत स्वीकार्य गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए एक विस्तृत ढांचा पेश किया गया है और साथ ही भारत में विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए अनुपालन आवश्कताओं को सख्त किया गया है।यह संशोधन फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंड रूल्स, 2011 में बदवाल करता है और एक विशेष अनुसूची पेश करता है जिसमें धार्मिक उद्देश्यों के तहत पंजीकरण के लिए पात्र गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है। सूचीबद्ध गतिविधियों में पूजा स्थलों जैसे- मंदिर, मस्जिद, चर्चा, गुरुद्वारों, मठ, सिनेगॉग और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण, नवीनीकरण और रखरखाव शामिल है।इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों और टीकाओं के संरक्षण, मुद्रण, अनुवाद और डिजिटलीकरण, धार्मिक दर्शन एवं इतिहास के अध्ययन से जुड़े संस्थानों को समर्थन, तथा तीर्थयात्रियों के लिए पेयजल, स्वच्छता और आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अनुमति दी गई है। नियमों के तहत धर्मशाला, लंगर, अन्नदान और सामुदायिक रसोई जैसी गतिविधियां भी धार्मिक उद्देश्यों के अंतर्गत मान्य होंगी।

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र में बैगा बाहुल्य क्षेत्र के सघन दौरा किया। जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की और अपने चिर परिचित अंदाज में जमीन में बैठकर आत्मीयता के साथ उनसे चर्चा की। उन्होंने उनकी समस्या और मांगो को सुना और अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए निर्देशित किया।

पद्म श्री से नवाजे गए रोहित शर्मा और सविता पूनिया

नईदिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को पद्म अवॉर्ड्स दिए। वहीं, दिग्गज भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को पद्म भूषण सम्मान और महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान सविता पूनिया को पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के भगवानदास रायकवार को मरणोप्रांत पद्म श्री पुरस्कार दिया गया।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी थी, जिसमें खेल जगत के कई दिग्गजों को शामिल किया गया था। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को कुछ दिन पहले पद्मश्री से नवाजा गया था। हरमनप्रीत कौर को उनके शानदार नेतृत्व और उपलब्धियों के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया था। साल 2025 उनके करियर के लिए बेहद खास रहा था, जब उन्होंने घरेलू सरजमीं पर भारतीय महिला टीम को विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई और देश का नाम रोशन किया। रोहित ने 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में वह भारत के अहम खिलाड़ी बने रहे। पिछले साल उन्होंने वनडे प्रारूप में 650 रन बनाए और टीम के लिए लगातार योगदान दिया। रोहित के ही नेतृत्व में भारत ने टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के खिताब जीते थे।भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया को भी पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने लंबे समय तक भारतीय महिला हॉकी टीम की रक्षा पंक्ति को मज़बूती दी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया। वहीं, विजय इस साल पद्म भूषण पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

प्रमुख समाचार

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह अल्पसंख्यक कार्य, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका छह साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा।

राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। जॉर्ज कुरियन मूल रूप से केरल के कोट्टायम जिले के रहने वाले हैं। वे मध्य प्रदेश से अगस्त 2024 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। जॉर्ज कुरियन जून 2024 से प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल वाले मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। इससे पहले वे मार्च 2017 से मार्च 2020 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वह भाजपा के अनुभवी नेताओं में शामिल हैं, जो 1980 में पार्टी की स्थापना के समय से ही इसके सदस्य रहे हैं। राजनीति में सक्रिय रहने के साथ-साथ उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भी काम किया है।

डॉ. श्यामा प्रसाद के बलिदान दिवस पर शुभेंदु ने दी श्रद्धांजलि

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दक्षिण कोलकाता स्थित केओरतला श्मशान घाट में मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता और उद्योग मंत्री तापस रॉय भी उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी अटूट निष्ठा, साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, बलिदान दिवस पर मैं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह एक विशिष्ट राष्ट्रभक्त, विद्वान और राजनेता थे, जिन्होंने अपना जीवन भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिया। सार्वजनिक जीवन में उनकी अटूट निष्ठा, साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

कांग्रेस की मोदी को सलाह ट्रंप को खुश करना बंद करें

नई दिल्ली। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत के दौरे पर आए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने अच्छे दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना बंद करना चाहिए। पार्टी के मुताबिक, भारत को

किसी ऐसे व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई जरूरत नहीं है जो देश के हितों के खिलाफ हो। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को मलेशिया से प्रेरणा लेनी चाहिए। मलेशिया ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका के साथ अपना व्यापार समझौता रद्द कर दिया था। रमेश ने बताया कि छह फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका ने व्यापार पर एक साझा बयान जारी किया था। उस समय राहुल गांधी ने संसद में चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर टैक्स 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का वादा किया था।

बंगाल सरकार खंगाल रही ममता बनर्जी की खाता-बही

कोलकाता। तृणमूल के फ्रीज किए गए बैंक खातों की जांच शुरू हो गई है। बिधाननगर पुलिस स्टेशन ने तीनों खातों से संबंधित जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने उन निजी बैंक से कई जानकारियां मांगी हैं, जहां ये तीनों खाते स्थित थे। जांचकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की है कि

बैंक खाते कब खोले गए थे, उन्हें खोलने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और ये खाते किसके नाम पर हैं। तीनों खातों के पिछले पांच वर्षों के विवरण मांगे गए हैं। यानी जांचकर्ता यह देखना चाहते हैं कि किन खातों से उस बैंक खाते में पैसा आया और कितनी रकम जमा हुई, क्योंकि तृणमूल के खातों में कई संदिग्ध लेनदेन होने और गबन की गई रकम जमा होने के आरोप लगे हैं। बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन पूरे मामले की जांच कर रहा है। तृणमूल के तीन खातों में पहले ही 440 करोड़ रुपये फ्रीज किए जा चुके हैं। हालांकि, कालीघाट तृणमूल इस मामले में हाई कोर्ट का रुख करने जा रही है।

शरद पवार की एनसीपी पर भाजपा की नजर!

मुंबई। तृणमूल कांग्रेसके 20 सांसदों और उसके बाद शिवसेना के छह लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के बाद, मीडिया और राजनीतिक जानकारों की नज़र अब एनसीपी पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के आठ लोकसभा सांसदों में से पांच, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इन अटकलों की वजह से पवार के एनसीपी गुट पर भारी दबाव बन गया है। रिपोर्टों के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुनेत्रा पवार की हालिया मुलाक़ात ने इन अफ़वाहों को और हवा दी है। एनडीए संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड और परिसीमन बिल जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को पास किया जा सके। ऑपरेशन टाइगर के बढ़ते खतरे को देखते हुए, शरद पवार ने 19 जून को अपने बचे हुए नेताओं की एक ज़रूरी बैठक बुलाई। ऑपरेशन टाइगर के तहत नेताओं के पाला बदलने के डर का सामना करने और राज्य में गठबंधन की रणनीति बनाने के लिए, 24 जून को मुंबई में एएमवी विधायकों की आम बैठक होगी। कांग्रेस राज्य में होने वाले आगामी राजनीतिक मुकाबलों से पहले विपक्षी गुट के भविष्य को मज़बूत और सुरक्षित करने के लिए के साथ संभावित रणनीतिक विलय पर चर्चा कर रही है।

अपना बोया ही काट रही ममता बनर्जी

डॉ. आशीष वशिष्ठ

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक पराजय के बाद, जिस तरह पार्टी के विधायक और सांसद ममता बनर्जी से नाता तोड़ रहे हैं, उसने कई लोगों को हैरान किया है। लेकिन ममता बनर्जी पिछले 28-29 सालों से जिस तरह की सिद्धान्तहीन राजनीति करती रही हैं, उसे देखते हुए इन जन-प्रतिनिधियों के कारनामे कुछ भी असामान्य नहीं लगते। वे बस वही कर रहे हैं जो ममता दीदी ने उन्हें सिखाया है। असल में, अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु के दिखाए रास्ते पर चले। ये सांसद और विधायक भी वही कर रहे हैं जो ममता बनर्जी करती रही हैं, यानी बिना किसी सिद्धांत या आदर्शवादी राजनीति। किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना और काम निकल जाने पर उसे छोड़ देना, बार-बार उससे मुंह मोड़ लेना और विपक्षी पार्टियों के विधायकों पर हमला करना।

तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों और सांसदों पर मुख्य आरोप यह है कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद, वे अब विपक्षी भाजपा के साथ मिल रहे हैं, वही भाजपा, जिसे उन्होंने चुनाव के दौरान सांप्रदायिक पार्टी बताकर हराया था। लेकिन ममता बनर्जी ने भी 1998 में ऐसा ही किया था, जब उन्होंने 1 जनवरी 1998 को कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। उस समय ममता बनर्जी को कांग्रेस से यह शिकायत थी कि राज्य में लेफ्ट फ्रंट को हराने के लिए कांग्रेस भाजपा के साथ हाथ क्यों नहीं मिला रही है? उस समय ममता भाजपा को सांप्रदायिक नहीं मानती थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि भाजपा कोई सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। तो, अगर अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक कह रहे हैं कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, तो इसमें क्या गलत है? वे बस अपनी प्रिय नेता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चार बार (2013, 2017, 2022 और 2024 में) अपना पक्ष बदला, लेकिन ममता बनर्जी अब तक पांच बार अपना पक्ष बदल चुकी हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो, बात 1997 की है, केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी। संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, नतीजतन नवंबर 1997

में सरकार गिर गई और 1998 में नए सिरे से लोकसभा चुनाव हुए। तब तक ममता कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बना चुकी थीं। चुनावों में ममता की तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के साथ सीट का समझौता किया और सात सीटें जीतीं। हालांकि, वह सरकार में शामिल नहीं हुईं क्योंकि उन्होंने राज्य में अपनी नई बनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दिया। 13 महीने बाद केंद्र सरकार गिर गई।

1999 के चुनावों के बाद एक नई सरकार बनी, जिसमें ममता बनर्जी रेल मंत्री बनीं। 2001 में, जब बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक थे, तो ममता को लगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना फायदेमंद रहेगा। इसलिए, मार्च 2001 में उन्होंने रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले (तहलका स्टिंग ऑपरेशन) का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हालांकि, इससे भी बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को हराया नहीं जा सका। लेफ्ट फ्रंट ने 199 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 31 प्रतिशत वोट के साथ सिर्फ़ 60 सीटें मिलीं।

अगले विधानसभा चुनाव में अभी पांच साल बाकी थे और केंद्र में भाजपा की सरकार थी। इसलिए, 2003 में ममता बनर्जी फिर से वाजपेयी सरकार में शामिल हो गईं। वह सितंबर 2003 में वाजपेयी सरकार में मंत्री बनीं, जबकि गुजरात दंगे डेढ़ साल पहले, यानी फरवरी 2002 में हो चुके थे। उन्होंने दंगों के लिए गुजरात में मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन जब अप्रैल 2002 में लोकसभा में वाजपेयी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, तो ममता की पार्टी ने वाजपेयी का समर्थन किया। इस समर्थन के बदले, कुछ महीनों बाद उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया।

ममता बनर्जी ने 2004 के लोकसभा और 2006 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़े। हालांकि, जब उनकी पार्टी को दोनों चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनावों में तृणमूल को सिर्फ एक सीट मिली और 2006 के विधानसभा चुनावों में न सिर्फ पार्टी का वोट शेयर घटा (26 प्रतिशत हो गया) बल्कि उसकी सीटें भी आधी रह गईं, तो ममता को लगा कि भाजपा के साथ गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं है। केंद्र में भाजपा के सत्ता से बाहर होने के बाद, ममता बनर्जी ने फिर से कांग्रेस पार्टी का रुख किया। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़े। तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीटें जीतीं। इस जीत से उत्साहित होकर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 2011 का विधानसभा चुनाव लड़ा और सरकार बनाई।

सरकार बनाने के ठीक एक साल बाद, ममता ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अब कांग्रेस की सीढ़ी की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह यहीं नहीं रुकीं।

4.02 करोड़ के निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा

कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, डिप्टी सीएम ने बताया तकनीकी चूक

मुंगेली। जिले में अमरटापू धाम और भरवागुड़ा को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे करोड़ों रुपये की लागत वाले पुल का स्लैब गिरने का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का विषय बन गया है। घटना का एक लाइव वीडियो सामने आने के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि निर्माणाधीन पुल पर मटेरियल से लदी एक गाड़ी आगे बढ़ती है। जैसे ही वाहन स्लैब के ऊपर पहुंचता है, संरचना पर दबाव बढ़ जाता है और कुछ ही क्षणों में स्लैब भरभराकर नीचे गिर पड़ता है। घटना के समय पुल पर कई श्रमिक काम कर रहे थे, जो समय रहते वहां से हट गए। इससे एक बड़ा हादसा टल गया।वायरल वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि निर्माणाधीन पुल का स्लैब एक लोडेड वाहन का दबाव नहीं झेल सका, तो भविष्य में इसकी मजबूती और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होना स्वाभाविक है। मुंगेली दौरे पर पहुंचे कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान इस घटना को गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री का यह गृह जिला है और यदि मंत्री के गृह जिले में ही निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिर रहा है, तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अटल श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया जाएगा।

4 करोड़ 2 लाख रुपये की है परियोजना

जानकारी के अनुसार अमरटापू धाम से भरवागुड़ा को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण लगभग 4 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस कार्य का आदेश दिसंबर 2024 में जारी किया गया था और छह माह के भीतर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। परियोजना में देरी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य में बिना माइनिंग विभाग की अनुमति के मिट्टी उपयोग किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं।

मामले पर उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मटेरियल से लदी गाड़ी निर्धारित सीमा से आगे बढ़ गई थी, जिससे स्लैब पर अतिरिक्त दबाव पड़ा और वह गिर गया। अरुण साव ने कहा कि घटना को जिस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है, वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक की जानकारी में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की बात सामने नहीं आई है। उनके अनुसार यह निर्माण कार्य के दौरान हुई एक तकनीकी चूक है और ऐसे कार्यों में कभी-कभी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। फिलहाल पूरे मामले में विभागीय जांच की प्रक्रिया जारी है। एक ओर विपक्ष निर्माण गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं सरकार इसे तकनीकी त्रुटि बता रही है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे पुल का स्लैब किन परिस्थितियों में गिरा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है।

कांकेर के आमाटोला जंगल में मिला नक्सलियों का विस्फोटक डम्प

4 बंदूक, 2 वायरलेस सेट समेत कई सामान बरामद

कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षाबलों को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्च अभियान के दौरान आमाटोला के जंगल में नक्सलियों का खुफिया डंप बरामद हुआ है। जहां हथियार समेत अन्य नक्सल सामान छिपाकर रखी गई थी। यह पूरी कार्रवाई कांकेर पुलिस, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम ने की है। जानकारी के अनुसार, वरीष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार संयुक्त अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को छोटेबेठिया थाना क्षेत्र के आमाटोला के पास जंगल में सर्चिंग के दौरान जवानों को कुछ संधिग्ध नजर आया। जांच में नक्सलियों का विस्फोटक डंप मिला, जिसमें से कई नक्सल सामान बरामद किया गया है। नक्सल साहित्य के अलावा अन्य नक्सल सामग्री बरामद किया गया। जिसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। अभियान के बाद सभी जवान वापस कैंप लौट आए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि जिले के संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्रों में आगे भी संयुक्त सर्च अभियान लगातार जारी रहेंगे।

नक्सल डंप से क्या-क्या मिला

भारमार बंदुक-04 नग, वायरलेस सेट-02, रेडियो-01नग, नक्सल वर्दी-01नग, पोच-02 नग, चार्जर-01नग, बैटरी-01नग।

मनरेगा में फर्जी अटेंडेंस और डीएमएफ सड़क में घोटाले का आरोप, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बलौदा बाजार। कसडोल जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत भुसड़ीपाली में विकास कार्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम पंचायत की उपसरपंच ने मनरेगा और डीएमएफ मद के कार्यों में गंभीर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अपनी शिकायतों को लेकर उपसरपंच और पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के नाम शिकायत पत्र सौंपते हुए जांच की मांग की।

उपसरपंच के साथ जिला मुख्यालय आए ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा के तहत स्वीकृत सोनझोला नाला सफाई कार्य में फर्जी हाजिरी लगाकर मजदूरी राशि निकाली गई, जबकि कई ऐसे लोगों के नाम मस्टररोल में दर्ज किए गए जिन्होंने मौके पर कोई काम ही नहीं किया। वहीं डीएमएफ मद से निर्मित सीसी रोड में भी गुणवत्ता से समझौता कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप उपसरपंच और ग्रामीणों ने लगाया है। ग्राम पंचायत की उपसरपंच लता लोधवंशी ने कहा कि मनरेगा कार्यों में वास्तविक मजदूरों के बजाए कुछ लोगों को केवल फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया जाता था। बाद में उन्हीं लोगों के नाम से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कर मजदूरी निकाली जाती थी। उपसरपंच का आरोप है कि जब पंचों ने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। लता लोधवंशी ने दावा किया कि कई ऐसे लोगों की हाजिरी दर्ज हुई है जो कभी कार्यस्थल पर काम करने पहुंचे ही नहीं।

शासन-प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार, तो ग्रामीण ने खुद के पैसे से बना लिया पुल

गरियाबंद। तहसील मुख्यालय मैनपुर नगर के स्टाप डेम मोहल्लावासी पिछले 20-25 सालों से बारिश के चार माह बेहद ही दयनीय स्थिति में गुजारने को मजबूर होते हैं।

मैनपुर नगर से गजरने वाली फुलझर नदी के उस पार ग्राम पंचायत मैनपुरकला के वार्ड क्रमांक 01 में लगभग 30-35 परिवार निवास करते हैं और इस मोहल्ले के लोग बारिश के दिनों में जर्जर हो चुके 20 फीट गहरे जानलेवा स्टापडेम को छलांग लगाकर पार करने को मजबूर होते हैं।

इतना ही नहीं मैनपुर के स्कूलों में पढ़ने वाले इस मोहल्ले के छोटे-छोटे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर आना जाना करते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किसी के तबीयत खराब होने पर या फिर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक लाने में उठानी पड़ती है। ग्रामीण मैनपुर नदी में पुल निर्माण की मांग को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुके और तो और इस मामले को लेकर कई बार जनपद से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन ग्रामीणों के इस मांग की तरफ अब तक ध्यान नहीं दिया गया।

स्टापडेम मोहल्ले के मुर्गा व्यवसायी लोचन चक्रधारी ने अपने खुद के खर्च से लगभग 10 से 12 लाख रूपये खर्च कर अपने घर के सामने नदी मे पुल का निर्माण कर दिया और पुल निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है।

आने वाले बारिश में इसका लाभ इस मोहल्ले के लोगों को मिलेगा। इस ऐतिहासिक कार्य का क्षेत्र के लोगों द्वारा जमकर प्रशंसा की जा रही है।

पुल निर्माण कर मिशाल पेश करने वाले ग्रामीण लोचन चक्रधारी ने बताया कि कई बार शासन-प्रशासन से मोहल्ले वाले पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इस तरफ ध्यान नही दिया जबकि यह तहसील मुख्यालय है और यहां से महज 200 कदम की दूरी पर जनपद और एसडीएम कार्यालय है बावजूद इस मोहल्ले के छोटे - छोटे बच्चे जान जोखिम मे डालकर स्कूल आना जाना करने मजबूर हो रहे है।

चक्रधारी ने बताया लोगों की समस्या और उनके परिवार की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने मैनपुर नदी में अपने स्वयं का लगभग 10 से 12 लाख रूपये खर्च कर पुल का निर्माण किया है जिसमें उन्होंने दुकानदारों से कर्ज लिया है साथ ही उन्हें धीरे-धीरे कर्ज चुकाने की बात कहते हैं। पुल के एप्रोज में मुरमीकरण कार्य बचा हुआ है।

3 करोड़ 20 लाख लीटर गंदे पानी का अंबिकापुर करेगा री-यूज

सरगुजा। अंबिकापुर अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा है। 32 एमएलडी का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। अंबिकापुर के सेनेटरी पार्क में प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। इस प्लांट के जरिये अब शहर में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जायेगी और भू जल स्तर के साथ साथ गंगा बेसिन के नियमों को पूरा करते हुये, नदियों में साफ पानी बहाया जाएगा। कंपनी के इंजीनियर आलोक यादव ने बताया कि यहां ट्रीट किया गया पानी एग्रीकल्चर, फायर और सिंचाई के लिए यूज होगा। पानी पीने के योग्य नहीं होगा।

इसमें जो टीडीएस होता है, उसकी मात्रा काफी होती है, इसलिए हम इसका उपयोग पीने योग्य नहीं कर सकते। पूरे अंबिकापुर का पानी यहां आयेगा। यहां पर फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री होती तो उसके लिए डब्ल्यूटीपी बनाते। एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। मतलब अंबिकापुर के डोमेस्टिक यूज का पानी है, जिसे शुद्ध किया जाएगा- आलोक यादव, इंजीनियर स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी रितेश सैनी ने बताया कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में अभी एसटीपी का निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान अंबिकापुर नगर निगम जो क्षेत्र है, इसमें जो पानी का वास्तविक ढलान है, वह शहर की तीन दिशा की ओर जाता है। तीन नालों के माध्यम से शहर का बाहर पानी जा रहा है। चाहे वो शहर के नालियों का पानी हो या बरसाती पानी हो। इसमें अभी जो दूषित पानी है, जिसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए तीन एसटीपी प्लांट निर्माणधीन हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

8 दिनों में सुलझी हत्या की गुत्थी बेटा ही निकला पिता का हत्यारा

सूरजपुर। रामानुजनगर पुलिस ने आठ दिनों के भीतर एक सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 45 वर्षीय व्यक्ति की हत्या उसके ही बेटे ने की थी और अपने मौसा और दोस्त की मदद से शव को बोरे में बांधकर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया था। पूरा मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चिरमी बचरापोड़ी का है। पुलिस के अनुसार, 10 जून की रात हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और 11 तारीख की रात आरोपियों ने शव को बोरे में भरकर फेंक दिया था। दो दिन पहले शव की पहचान 45 वर्षीय शिव प्रसाद सिंह (गोंड), निवासी चिरमी बचरापोड़ी, थाना बैकुंठपुर के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि शिव प्रसाद सिंह की हत्या उसके घर चिरमी परसापारा में ही की गई थी। आरोपियों ने टांगी और लोढ़ा से वार कर मौत के घाट उतारा था। इसके बाद शव को बोरे में बांधकर दूसरे स्थान पर ले जाकर फेंक दिया गया, ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की साजिश मृतक के बेटे ने रची थी।

नारायणपुर जिले में ईसाई और आदिवासी समाज आमने-सामने

नारायणपुर। जिले के भरण्डा गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद गहरा गया है। सुबह से गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार, करीब 26 मतांतरित परिवारों का आरोप है कि गांव के आदिवासी ग्रामीणों ने उन्हें गांव छोड़ने का फरमान जारी किया है। उनका कहना है कि उनसे ईसाई धर्म का पालन छोड़कर आदिवासी रीति-रिवाज अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। परिवारों का दावा है कि उन्हें घरों से बाहर निकालने की कोशिश की गई। वहीं, आदिवासी समुदाय का कहना है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले कुछ लोग गांव की पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाज और देवी-देवताओं का अपमान करते हैं। समुदाय का कहना है कि यदि वे गांव में रहना चाहते हैं तो उन्हें आदिवासी परंपराओं का सम्मान करना होगा अन्यथा गांव छोड़ना होगा। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर कहासुनी और झूमाझटकी हुई।

अपराध बढ़ने को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन और घेराव

पंडरिया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पंडरिया विधायक और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध वसूली के चक्कर में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। रैली की शक्ल में प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग की। आदिवासी परिवार के शख्स का नरकंकाल मिलने की घटना से भी नाराज कांग्रेस ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। नाराज कार्यकर्ताओं ने पंडरिया विधायक का पुतला दहन कर अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन का आयोजन पंडरिया नगर वार्ड 11 धूलियापाार में किया था। प्रदर्शन का नेतृत्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रभान बारमाते ने किया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में पीड़ित आदिवासी परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। थाने का घेराव करने के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स फांदकर आगे बढ़ने लगे।

उदंती-सीतानदी में बाघों की वापसी का शुरू हो सकता है सिलसिला

धमतरी। गरियाबंद उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व से वन्यजीव संरक्षण को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। हाल के दिनों में रिजर्व क्षेत्र में कैमरा ट्रैप, ग्रामीणों द्वारा बनाए गए वीडियो और तस्वीरों में एक बाघिन की मौजूदगी दर्ज की गई है। इस सुखद घटनाक्रम ने वन विभाग, वन्यजीव विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है कि उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में बाघों की स्थायी वापसी की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व लंबे समय से बाघों की संख्या में कमी की चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में किसी बाघिन की सक्रिय मौजूदगी केवल एक वन्यजीव के दिखाई देने की घटना नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ जैसे शिकारी की उपस्थिति किसी भी जंगल के स्वस्थ और संतुलित होने का प्रमाण है। उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने कहा, अभ्यारण्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली बाघिन की उम्र लगभग 4 वर्ष आंकी गई है।

चोरी के शक में हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार

एमसीबी। मनेंद्रगढ़ के बिछली गांव में चोरी के शक में युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से युवक की मौत हो गई जबकि घटना में एक महिला गंभीर रुप से जख्मी हुई। पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने बताया कि घटना 14 जून की है। आरोपियों ने चोरी का इल्जाम लगाते हुए बिछली गांव में राजकुमार नाम के शख्स की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद जख्मी हालत में राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 14 जून की रात बिछली गांव में कुछ लोगों ने पति-पत्नी को चोरी के शक में पकड़ लिया था और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की थी। मारपीट में पति राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया।

मौत के साए में पढ़ाई, जर्जर स्कूल भवनों में बैठने को मजबूर बच्चे

खैरागढ़। खैरागढ़ जिले में नए शैक्षणिक सत्र की घंटी तो बज चुकी है, लेकिन कई स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई अब भी खतरे के साए में चल रही है। कहीं दीवारों में गहरी दरारें हैं, तो कहीं छतें जर्जर होकर कभी भी भरभराकर गिरने की स्थिति में हैं। बरसात शुरू होते ही इन स्कूल भवनों की हालत ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि आखिर बच्चों की पढ़ाई कब तक ऐसे खतरनाक भवनों के भरोसे चलती रहेगी? जिले के कई शासकीय स्कूल वर्षों से खस्ताहाल भवनों की समस्या से जूझ रहे हैं।

बारिश के दौरान छतों से पानी टपकना, प्लास्टर झड़ना और कमजोर दीवारों का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में हर दिन स्कूल पहुंचने वाले मासूम विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मरम्मत और नए भवन की मांग की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका है। हालांकि, शिक्षा विभाग का दावा है कि जिन भवनों को अत्यधिक जर्जर और बच्चों के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है, वहां कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। ऐसे स्कूलों को पंचायत भवन, सामुदायिक भवन या अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

जिला शिक्षा अधिकारी (ष्ठश्वह्) मुकुल साव के अनुसार, जिले में जर्जर भवनों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने 37 स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए राशि भी जारी कर दी है और जल्द कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है कि क्या मरम्मत की प्रक्रिया किसी हादसे से पहले पूरी हो पाएगी या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? क्योंकि जिन स्कूलों में भविष्य गढ़ा जाता है, वहां बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

पावर कंपनी के कर्मचारी अधिकारी 21 सूत्रीय मांगों पर अड़े

छत्तीसगढ़ राज्य के पावर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन ने सामूहिक अवकाश लेकर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया है.

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य के पावर कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के संगठन ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। पावर कंपनी तीन अलग-अलग कंपनियों जनरेशन, ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन में विभाजित है। इन सभी कंपनियों में काम करने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों का छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन है।

इसी संगठन ने कोरबा जिले के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिसके लिए उन्होंने मास सीएल लिया था। संगठन का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों की अवहेलना कर रही है, कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार किया जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह हड़ताल केवल कोरबा में नहीं है। बल्कि जहां-जहां पावर कंपनी के पावर प्लांट हैं, दफ्तर हैं उन सभी स्थानों पर आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल मास सीएल लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि मांगों को अनसुना किया गया, तो लगातार आंदोलन किए जाएंगे। संगठन ने यह भी जानकारी दी कि उनकी 21 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लगातार अनसुना किया जा रहा है। संगठन के सचिव देवी शंकर राय ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। इस संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया था कि 3 महीने के भीतर प्रमोशन का डाटा इकट्ठा करके कोर्ट के दिए गए निर्देश के अनुसार नियम बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। संघठन के मुताबिक 20 साल पुराना 2004 की स्थिति में ग्रेडेशन को पब्लिश किया गया है। इसी को आधार मानकर प्रमोशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी बाइपास किया गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। शासन को मांगों को मनाना होगा अन्यथा भविष्य में बड़ा आंदोलन होगा।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री ने बलिदान दिवस पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद्, भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उनके विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र एवं राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र की अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर ही हम राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, श्री राम गर्ग सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल ने दी श्रद्धांजलि

रायपुर। प्रखर राष्ट्रवादी नेता एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को लोक भवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और को सुदृढ़ करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनके विचार और आदर्श आज भी देशवासियों को राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। लोक भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगी निःशुल्क शिक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित 'अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना' के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 03 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित की गई है। जिला श्रम अधिकारी बालोद ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियो को प्रदेश के निजी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बालोद जिले को इस वित्तीय वर्ष मे 07 सीटों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक निर्माणी श्रमिक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए 03 जुलाई 2026 तक ऑनलाईन आवेदन श्रमेव जयते मोबाइल एप्प के माध्यम से कर सकते हैं।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान राष्ट्र की एकता और अखंडता का अमर प्रतीक

रायपुर। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के

बलिदान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय रायपुर के एकात्म परिसर एवं शारदा चौक स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हे श्रद्धांजलि आर्पित किया। संजय श्रीवास्तव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्तिए त्याग और अखंड भारत के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। डॉ. मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनका स्पष्ट मानना था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चल सकते। राष्ट्रहित के लिए उनके संघर्ष और बलिदान ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद्ए प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने देश के युवाओं में राष्ट्रप्रेमए कर्तव्यनिष्ठा और सेवा की भावना जागृत करने का कार्य किया। उनका जीवन आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत है।

खनिज संपदा की नई उपलब्धि से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगा नया आयाम: साय

महासमुंद के बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरों की प्राप्ति से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगा गति

रायपुर। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरों की प्राप्ति ने प्रदेश को खनिज संपदा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण एवं प्रसंस्करण के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त हुए हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है। यह उपलब्धि क्षेत्र में हीरा खनिजीकरण की संभावनाओं की पुष्टि करती है तथा भविष्य में बड़े पैमाने पर निवेश, राजस्व सृजन और रोजगार के नए अवसरों का आधार बन सकती है।

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा राज्य शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र में किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय अध्ययन तथा अन्वेषण ड्रिलिंग के आधार पर चिन्हित क्षेत्र से लगभग 200 टन खनिज सामग्री का बल्क सैंपल एकत्रित कर परीक्षण किया गया। प्रसंस्करण के पश्चात प्राप्त पांच हीरों में दो जेम क्वालिटी तथा तीन अन्य श्रेणी के हीरे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, पारदर्शी प्रबंधन और मूल्य संवर्धन आधारित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले से ही देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है और लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हीरा संभावनाओं की पुष्टि से प्रदेश की खनिज विविधता और अधिक समृद्ध होगी तथा खनिज अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीति केवल खनिजों के उत्खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि खनिज आधारित उद्योगों, मूल्य संवर्धन इकाइयों और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रदेश में खनिज संसाधनों के माध्यम से निवेश, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार खनिज, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर रही है। बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र से प्राप्त यह सफलता प्रदेश की खनिज क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी तथा निवेश, रोजगार और समावेशी विकास के नए द्वार खोलेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैज्ञानिक अन्वेषण और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेश के अन्य संभावित क्षेत्रों में भी खनिज संपदा की खोज को गति मिलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक चरण में प्राप्त यह सफलता भविष्य के विस्तृत अन्वेषण कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इससे क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना, संसाधन क्षमता और संभावित भंडारों के संबंध में व्यापक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होगा। आगामी सर्वेक्षणों एवं परीक्षणों से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का अधिक सटीक आकलन किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में किए गए बल्क सैंपल परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त हीरों को सुरक्षित अभिरक्षा में एनएमडीसी के पन्ना स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है तथा आगे की कार्यवाही नियमानुसार और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील सोच से परिवार को मिला संबल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राज्य शासन संवेदनशील और जनहितकारी प्रशासन को प्राथमिकता दे रहा है। इसी सोच का एक प्रेरणादायक उदाहरण छत्तीसगढ के बीजापुर जिले में देखने को मिला, जहां कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे एक परिवार को समय पर सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई गई। बीजापुर जिले के विकासखंड उसूर स्थित कन्या आश्रम भट्टीगुड़ा में आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत भृत्य पद पर कार्यरत स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी बुरका के निधन के बाद उनके परिवार के सामने आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो गईं। परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मानवीय एवं संवेदनशील शासन व्यवस्था के अनुरूप जिला प्रशासन ने परिवार की परिस्थितियों को गंभीरता से समझा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। शासन के नियमों के तहत स्वर्गीय लक्ष्मी बुरका की पुत्री कुमारी पार्वती बुरका को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की गई। कलेक्टर श्री विश्वदीप के मार्गदर्शन तथा आदिवासी विकास विभाग के सहयोग से कुमारी पार्वती बुरका को भृत्य पद पर नियुक्ति आदेश सौंपा गया। नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद पार्वती बुरका और उनके परिवार के चेहरे पर नई उम्मीद और आत्मविश्वास दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति केवल रोजगार नहीं, बल्कि उनकी मां के सपनों और जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने का अवसर है। पार्वती ने पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का संकल्प व्यक्त किया। कुमारी पार्वती बुरका की कहानी यह बताती है कि शासन की संवेदनशील पहल और समय पर मिले सहयोग से कठिन परिस्थितियों में भी जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। अनुकंपा नियुक्ति ने न केवल एक परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है।

टिश्यू कल्चर तकनीक से किसानों को मिलेगा अधिक लाभ

उन्नत सागौन रोपण पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज अरण्य भवन, नवा रायपुर में मंगलवार को सागौन प्रबंधन एवं उन्नत सागौन रोपण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण पाण्डेय, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि सागौन (टीक) का प्रबंधन और उन्नत रोपण उच्च गुणवत्ता वाली इमारती लकड़ी के उत्पादन और शानदार मुनाफे का सौदा है स उन्होंने कहा कि सागौन विश्व की सबसे मूल्यवान इमारती लकड़ियों में से एक है। इसकी मजबूती, टिकाऊपन और दीमक-रोधी गुणों के कारण इसे लकड़ी का राजा कहा जाता है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग भविष्य की सुरक्षा के लिए बैंक में निवेश करते हैं, उसी तरह सागौन का पौधा लगाना भी एक दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश है। इससे किसानों को भविष्य में बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

वन मंत्री श्री कश्यप ने किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार सागौन के पौधे सामान्य पौधों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। इन पौधों का तना सीधा और गुणवत्तापूर्ण होता है, जिससे बेहतर गुणवत्ता की लकड़ी प्राप्त होती है और किसानों की आय बढ़ती है।

श्री कश्यप ने बताया कि किसान सागौन रोपण के शुरुआती वर्षों में पौधों के बीच खाली स्थान पर दलहन, तिलहन अथवा अन्य फसलें लेकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। वहीं 8 से 10 वर्ष बाद वृक्षों की छंटाई (थिनिंग) से भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा निजी भूमि पर व्यावसायिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान दिया जा रहा है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए 5 एकड़ तक सागौन रोपण पर 100 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके तहत प्रति पौधा 94.50 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करने वाले किसानों एवं संस्थाओं को 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

कार्यशाला में कोयम्बटूर से आईं प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. रेखा आर. वारियर और डॉ. आर. यशोदा ने किसानों को उन्नत सागौन उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने मिट्टी के चयन, पौधों की देखभाल, रोग प्रबंधन तथा टिश्यू कल्चर आधारित पौधों की विशेषताओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।

विशेषज्ञों ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी सागौन उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बीजापुर, भोपालपटनम, कोटा, अंबागढ़ चौकी, रायगढ़, सराईपाली और नारायणपुर सहित कई क्षेत्रों में सागौन आधारित कृषि वानिकी किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

कार्यशाला के समापन अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने किसानों से बड़े पैमाने पर सागौन रोपण अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि श्खेत में सागौन, हर किसान समृद्धश् का संकल्प प्रदेश में हरित विकास और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगा।

उप मुख्यमंत्री शर्मा की अनुशंसा पर कबीरधाम जिले के विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की अनुशंसा पर कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा द्वारा कवर्धा विधानसभा के अलग-अलग ग्रामों में निर्माण कार्या के लिए 01 करोड़ 64 लाख 69 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्य के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी कवर्धा, जनपद पंचायत कवर्धा, सहसपुर लोहारा, बोड़ला और विद्युत विभाग को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

उपमुख्यमंत्री व कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा की अनुशंसा से कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के पेयजल व्यवस्था एवं विद्युत पंप कार्य, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारंगपुरकला, ग्राम सारंगपुरकला राशि 0.70 लाख रुपए, बोर (नलकूप) खनन कार्य, वार्ड क्रमांक 13, ग्राम बोटेसुर, ग्राम पंचायत भेण्ड्रा-राशि 0.60 लाख रुपए, सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य, ग्राम पवनतरा राशि 2.00 लाख रुपए, रंगमंच निर्माण कार्य, ग्राम सुरजपुरा (जं.) राशि 5.00 लाख रुपए, मंच निर्माण कार्य, ग्राम सरईपतेरा, ग्राम पंचायत सोनझरी राशि 1.50 लाख रुपए, सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य, शीतला मंदिर के पास, ग्राम एवं ग्राम पंचायत बामी राशि 1.00 लाख रुपए, विद्युत पोल विस्तार कार्य, ग्राम गंडईखुर्द राशि 3.00 लाख रुपए, विद्युत पोल विस्तार कार्य (11 के.व्ही. तार स्कूल मैदान से स्थानांतरित), ग्राम राम्हेपुरखुर्द राशि 2.70 लाख रुपए, सी.सी. रोड निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 05, गुरुदास के घर से ओमप्रकाश के घर तक, ग्राम बोड़ला राशि 3.00 लाख रुपए, आंगनबाड़ी भवन मरम्मत कार्य, ग्राम खारा राशि 1.69 लाख रुपए रंगमंच निर्माण कार्य, ग्राम मिनमिनिया मैदान राशि 4.00 लाख रुपए, सामुदायिक भवन मरम्मत कार्य, सतनाम भवन के पास, ग्राम तिलई भाठ, ग्राम पंचायत रघ्घूपारा राशि 1.50 लाख रुपए, गौठान निर्माण कार्य, माँ बंजारी मंदिर के पास, ग्राम दुर्जनपुर राशि 2.00 लाख रुपए, मुरुम सड़क निर्माण कार्य, ग्राम खैरबनाखुर्द राशि 3.00 लाख रुपए, गौठान निर्माण कार्य, गौ अभ्यारण्य के पास, ग्राम सरेखा राशि 5.00 लाख रुपए, मंच निर्माण कार्य, ग्राम एवं ग्राम पंचायत मिनमिनिया मैदान राशि 4.00 लाख रुपए, आंगनबाड़ी भवन मरम्मत कार्य, ग्राम एवं ग्राम पंचायत बैहरसरी राशि 1.00 लाख रुपए, सी.सी. रोड सह नाली निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 15, बांधाटोला रोड, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा राशि 4.00 लाख रुपए। सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, वार्ड क्रमांक 14, कबीर कुटी के पास, शीतला मंदिर चौक, नगर पंचायत सहसपुर लोहारा राशि 6.50 लाख रुपये, रंगमंच निर्माण कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना बनी शहरी गरीबों के लिए संजीवनी

रायपुर। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजनामुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना शहरी गरीब एवं स्लम बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सूरजपुर जिला के नगर पंचायत जरही में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों ने हजारों जरूरतमंद परिवारों तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाकर जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत जरही में अब तक 463 स्वास्थ्य शिविरों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से 22,495 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। प्रत्येक शिविर में औसतन 49 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। योजना के अंतर्गत 5,635 लैब जांचें की गईं तथा 19,395 मरीजों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद नागरिकों को समय पर उपचार उपलब्ध हो सका।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत गैर-संचारी एवं गंभीर रोगों की शीघ्र पहचान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 536 नागरिकों की शुगर जांच की गई, जिनमें 86 मरीज मधुमेह से प्रभावित पाए गए। वहीं 21,603 लोगों का रक्तचाप परीक्षण किया गया, जिसमें 2,144 मरीज उच्च रक्तचाप एवं शुगर संबंधी समस्याओं से ग्रसित पाए गए।

चिन्हित सभी मरीजों को आवश्यक उपचार, निःशुल्क दवाइयां एवं विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया, जिससे रोगों की प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान और नियंत्रण संभव हो सका।

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर पर सियासी वार

भाजपा के पोस्टर पर विकास उपाध्याय का पलटवार

रायपुर। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को लेकर भाजपा द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी पोस्टर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में होने की वजह से भाजपा घमंड और मुगालते में है। राम मंदिर और धर्म के नाम पर पैसे कैसे चोरी करें, यह भाजपा का प्रशिक्षण है। बीफ कंपनियों से कैसे चंदा लेना है, यह भी भाजपा का प्रशिक्षण है।

दरअसल, भाजपा ने एक्स पर पोस्टर शेयर कर लिखा था कि कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में आज ढाई साल का झांसा देकर धोखा देना सिखाया जाएगा। इसके अलावा विकास उपाध्याय ने कैबिनेट की बैठक और काला दिवस मनाने पर बीजेपी पर निशाना साधा है।

साय कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा की सरकार समय पर कोई भी काम नहीं कर रही है। मानसून में किसानों को क्या मदद देनी चाहिए, यह अभी तक तय नहीं किया गया है। यूरिया खाद को लेकर किसान परेशान रहे। हर व्यक्ति आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला सरकार नहीं ले रही है, जिससे आम आदमी को राहत मिले।

25 जून को भाजपा द्वारा काला दिवस मनाए जाने को लेकर विकास उपाध्याय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा केंद्र में 12 साल से है। भाजपा किसी भी ज्वलंत मुद्दे को लेकर बात नहीं करती। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर व्यवस्था में भाजपा इस देश की जनता को कुछ नहीं दे रही।

सेंट पॉल स्कूल परिसर में चला बुलडोजर

रायपुर। राजधानी रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बने एक विवादित निर्माण को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया।

जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर में निर्मित एक भवन को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ था। हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वदिनी पांडेय ने आरोप लगाया था कि सामुदायिक भवन के नाम पर धार्मिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में शासन-प्रशासन से शिकायत करते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी।

शिकायत के बाद संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों और निर्माण की वैधता की जांच की गई। इसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर विवादित ढांचे को हटाने की कार्रवाई शुरू की। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी करते रहे। कार्रवाई के मद्देनजर सेंट पॉल स्कूल के आसपास के दोनों प्रमुख मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मौके पर अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, ताकि कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

शिकायतकर्ता विश्वदिनी पांडेय का दावा है कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया, उसकी लीज अवधि वर्ष 2022 में समाप्त हो चुकी थी। उनका आरोप है कि निर्धारित अनुमति के बिना निर्माण कराया गया और स्थानीय निकाय को भी इसकी विधिवत जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों को प्रशासनिक जांच में गंभीरता से लिया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई (छ.ग.)
Office Emall ID, eewrckn@cgwrd.In / Fax & Ph.No. 07743-263628

क्रमांक 2575 / व.ले.लि. छुईखदान, दिनांक 19/06/2026

-: शुद्धि पत्रः-

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा निरस्तीकरण आदेश क्र. 2483/व.ले.लि./2026, छुईखदान, दिनांक 11.06.2026 में उल्लेखित निविदा सूचना क्र. 02/व.ले.लि./2025-26, दिनांक 11.08.2026 को दिनांक 11.08.2025 पढ़ा जावे।

जी.नं. 262701440

कार्यपालन अभियंता,
जल संसाधन संभाग, छुईखदान

जी-262701615/9

सबसे मजबूत साबित हो रहा 'सत्ता का फैविकोल'

अकु श्रीवास्तव

इधर पिछले एक महीने में राजनीति की 3-4 बड़ी घटनाएं हुईं। पश्चिम बंगाल में बीते 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और मई अंत आते-आते तृणमूल कांग्रेस से 'तृण' अलग होने लगा और 15 दिन में ही सिर्फ 'मूल' बचा। तीन जून आते-आते टी.एम.सी. में औपचारिक रूप से विभाजन हो गया। 58 असंतुष्ट विधायकों ने अपने आपको मूल तृणमूल कांग्रेस बताया और कुछ ही दिन पहले पार्टी से निकाले गए ऋ्नुब्रत बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता बन गए। निशाना बने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी और पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी हो गए और एन.डी.ए. को समर्थन करने की घोषणा भी कर दी। यानी दो-तिहाई का मामला हुआ। कानूनी बाध्यता से मुक्ति मिली। बात यहीं तक नहीं रुकी। आजकल स्थानीय स्तर से लेकर तृणमूल विधायक और सांसद तक किसी बम से नहीं डर रहे। उनका डर अंडा हमले से है। ये अंडे कोई राजनीतिक दल से नहीं आ रहे। उन्हें यह भेंट ज्यादातर स्थानीय लोग ही कर रहे हैं, जो पिछले 10 साल से कटमनी का आतंक झेल रहे थे। जो सांसद-विधायक कभी अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, आजकल अपने चुनाव क्षेत्र में भी निकलने से डरते हैं। यही डर स्थानीय स्तर के नेताओं को भी है। दृश्य दो स्थान मुंबई। शिवसेना का मुख्यालय मातोश्री। जब तक बाल ठाकरे रहे, शेर दहाड़ता रहा लेकिन जबसे उद्धव ठाकरे आए, शेर धीरे-धीरे बूढ़ा होने लगा। राज ठाकरे के अलग होने के बाद तो यह गिरावट और तेजी से हुई। जिस मातोश्री में कभी शेर की शक्ति हुआ करती थी, दिसम्बर 24 में यह शक्ति भी चली गई। देवेंद्र फडनवीस के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी रणनीतिक रूप से दोफाड़ हो गई थी। बाकी लोकसभा में 9 सदस्यों वाली टी.एम.सी. की टूट के बाद ही शेर एक-तिहाई दुबला हो गया और 9 में से 6 सदस्य अलग हो गए। अब बस कुछ औपचारिकताओं का इंतजार है। वैसे भी सोमवार को एकनाथ शिंदे ने कह ही दिया है कि हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। यानी टूट की आगे और तैयारी है। हालांकि राजनीतिक दलों में टूट का यह सिलसिला पहली बार नहीं हुआ। हरियाणा का 'आया राम, गया राम' बदनाम हुआ जरूर लेकिन उसके बाद ऐसे कई और मौके आए तथा उदाहरण भी भारतीय राजनीति में मौजूद हैं। लेकिन ऊपर की टूट इसलिए अलग है क्योंकि यहां के नेताओं को सत्ता बहुत प्रिय भी है और वे सत्ता से डरते भी हैं। कर्नाटक में विधान परिषद चुनाव में कम से कम 11 भाजपा और जे.डी.एस. विधायकों ने पाला बदलकर कांग्रेस का साथ दिया। भाजपा का आरोप है कि सहयोगी जे.डी.एस. के कम से कम 8 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया है। इस उलटफेर से भाजपा और जे.डी.एस. के कर्नाटक के बड़े नाम पार्टी जांच के दायरे में आ गए हैं। इनमें जे.डी.एस. के जी.टी. देवेगौड़ा और एम.आर. मंजूनाथ तथा भाजपा के दिग्गज नेता रमेश जारकीहोली, बी.पी. हरीश, एम. चंद्रप्पा और एच.के. सुरेश शामिल हैं। तय है कि इन सभी गतिविधियों के पीछे सत्ता की मलाई के आदी नेताओं के निजी स्वार्थ और उलटे-सीधे धंधों तथा कमीशनखोरी पर सत्ता का नया पर्दा टांगने की कोशिश माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कटमनी कमीशन शब्द का पता अभी भला पूरे देश को चला हो लेकिन यह काफी लंबे समय से है और बदनाम भी। यह धंधा बिना सत्ता में रहे नहीं चल सकता। इसलिए जिधर सत्ता, उधर नेता का जाना स्वाभाविक हो गया है। सच तो यह है कि लोकतंत्र में 'सत्ता का फैविकोल' सबसे मजबूत साबित हो रहा है।

पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया तो भारत क्या करेगा?

नीरज कुमार दुबे

बड़बोले ख्वाजा आसिफ कभी भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं, कभी जल युद्ध की हुंकार भरते हैं और कभी देशी विदेशी मीडिया को दिए गए साक्षात्कारों में यह कबूल करते नजर आते हैं कि हर जंग में पाकिस्तान की फौज को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ताजा गीदड़ भभकी भी उसी बौखलाहट का नतीजा है, जो आतंकवाद के सहारे भारत को अस्थिर करने की नाकाम कोशिशों के बाद अब पानी के मुद्दे पर नया शोर मचा रही है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों ही अपने ही देश की नाकामियों को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रहे हैं।

हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़भभकी दी है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो इस्लामाबाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पानी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अगर जल आपूर्ति रोकने की दिशा में आगे बढ़ता है तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया था कि आतंकवाद और बातचीत अब साथ-साथ नहीं चल सकते।

उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु बेसिन से मिलने वाले जल से पाकिस्तान की करीब अस्सी प्रतिशत खेती चलती है। लेकिन दशकों तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को अब इस बात का डर सताने लगा है कि संधि स्थगित होने के बाद भारत अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत अपने अधिकार के पानी का इस्तेमाल बढ़ाएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर संकट और गहराता जाएगा।

साथ ही ख्वाजा आसिफ ने भारत पर चिनाब नदी के प्रवाह को हथियार की तरह इस्तेमाल करने और जल संबंधी सूचनाएं रोकने का आरोप लगाया है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई नहरों में भारी जल कमी दर्ज की गई है, जबकि पंजाब प्रांत पर तय हिस्से से ज्यादा पानी लेने के आरोप लग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के प्रांतों के बीच पानी को लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी अपने ही घर में जल संकट और अव्यवस्था संभालने में नाकाम पाकिस्तान अब भारत पर आरोप लगाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।

लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि यह पुराना भारत नहीं है। पिछले महीने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया था कि भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और यदि जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तीनों सेनाएं चौबीसों घंटे तैयारी कर रही हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल मजबूत किया जा रहा है और भविष्य के युद्ध की हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। जनरल द्विवेदी का यह बयान भारत की सैन्य शक्ति और आत्मविश्वास का परिचायक था। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध का मैदान पूरी तरह पारदर्शी हो चुका है, जहां दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सजग है।

पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब हर मोर्चे पर निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखता है। आतंकवाद, घुसपैठ, जल विवाद या सीमा पर उकसावे की हर हरकत का जवाब नए भारत की सेना उसी भाषा में देना जानती है। ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की कमजोरी और डर को उजागर करती हैं, जबकि भारतीय सेना का शौर्य, अनुशासन और तैयारी यह साबित करती है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस बार बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

फिर भी यदि मान लिया जाए कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिमाकत करता है तो सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? इसका जवाब यह है कि इस बार भारत की ओर से केवल सीमा पर जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को ऐसी मार झेलनी पड़ सकती है जिसकी कल्पना भी इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने नहीं की होगी। भारतीय सेनाध्यक्ष के बयानों के अलावा, दुनिया भर की रक्षा रिपोर्टों और सैन्य विश्लेषणों का अध्ययन बताता है कि पारंपरिक युद्ध क्षमता, आधुनिक हथियारों, आर्थिक ताकत, सैन्य तकनीक और रणनीतिक तैयारी के मामले में भारत पाकिस्तान पर कई गुना भारी पड़ता है।

हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे अनुभवी और विशाल सेनाओं में शामिल भारतीय थलसेना के पास सैनिक संख्या, आधुनिक तोपखाना, मिसाइल शक्ति और युद्धक टैंकों का ऐसा जाल है जो पाकिस्तान की जमीनी रक्षा को चंद दिनों में चरमरा सकता है। भारत के पास पिनाका बहु नली रॉकेट प्रणाली, धनुष तोप, च9ञ अजय टैंक, टी90 भीष्म टैंक और ब्रह्मोस जैसी घातक मारक क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। हाल के वर्षों में भारत ने स्वदेशी रक्षा निर्माण को तेजी से मजबूत किया है, जिसके कारण सेना को लगातार आधुनिक हथियार और तकनीक मिल रही है।

भारतीय सेना का सबसे बड़ा फायदा उसका वास्तविक युद्ध अनुभव और ऊंचे पर्वतीय इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना लंबे समय से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों से जूझ रही है। साथ ही भारत की रक्षा बजट क्षमता पाकिस्तान से कई गुना अधिक है, जिससे हथियारों की खरीद, तकनीकी उन्नयन और युद्ध तैयारी लगातार मजबूत होती जा रही है। साथ ही भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर है जबकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन और दूसरे देशों पर निर्भर है।

वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो यह वह ताकत है जो किसी भी आधुनिक युद्ध का रुख घंटों में बदल सकती है। भारतीय वायुसेना के पास रॉफेल, सुखोई तीस एमकेआई, तेजस और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। रॉफेल को दुनिया के सबसे खतरनाक बहुउद्देश्यीय युद्धक विमानों में गिना जाता है। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और अत्याधुनिक राडार प्रणाली पाकिस्तान के अधिकतर विमानों पर भारी पड़ सकती है। कई वैश्विक सैन्य अध्ययनों में माना गया है कि भारत की वायु शक्ति संख्या और तकनीक दोनों में पाकिस्तान से बहुत आगे है।

भारतीय वायुसेना की सबसे घातक ढाल एस-400 वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती है। हालिया सैन्य अभियानों और अभ्यासों में इस प्रणाली ने साबित किया कि पाकिस्तान की हवाई घुसपैठ या मिसाइल हमले को भारतीय रक्षा कवच के सामने टिकना बेहद कठिन होगा।

समंदर की बात करें तो भारतीय नौसेना पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमता पर भारी बढ़त रखती है। भारत के पास विमानवाहक पोत विक्रांत, परमाणु पनडुब्बी अरिहंत, अत्याधुनिक युद्धपोत, विध्वंसक जहाज और लंबी दूरी तक मार करने वाली समुद्री मिसाइलें हैं। भारतीय नौसेना अरब सागर में पाकिस्तान के बंदरगाहों और समुद्री आपूर्ति मार्गों को घेर सकती है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार पर निर्भर है और यदि भारतीय नौसेना ने नाकेबंदी कर दी तो पाकिस्तान के लिए ईंधन, हथियार और व्यापारिक आपूर्ति बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, भारत की सबसे बड़ी ताकत केवल हथियार नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के बीच बढ़ता तालमेल भी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत भविष्य के युद्ध के लिए चौबीसों घंटे तैयारी कर रहा है और तीनों सेनाएं मिलकर समन्वित युद्ध रणनीति पर काम कर रही हैं। आधुनिक निगरानी प्रणाली, सूचना युद्ध, उपग्रह क्षमता और त्वरित हमला करने की तैयारी भारत को निर्णायक बढ़त देती है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

महाशय जी ने बहुत कुछ कसर व्योंत करने के बाद बीच बीच से काट छांटकर भी जो प्रमाण प्रश्न में उपस्थित किये हैं उनमें भी कई ऐसे शब्द आ गये हैं जो महाराय जी के किये आक्षेप पर पानी फेरते है यथा-श्लोक 56 में शान्त क्या विषय-वलान्त और पढ़े लिखे मनुष्य ही कामकला में प्रवीण होते हैं? महाशय जी के भावानुसार तो यहाँ पुष्टं कोकशास्त्रविचक्षणम् होना चाहिये था। हम नहीं समझते कि कर्मानन्द जी ने भोगेच्छा अर्थ किस श्लोक के किस पदका कर डाला है? मूल में तो इसकी गन्ध भी नहीं है। संभवतः यह आप की ही खोपड़ी की उपज है। क्योंकि आर्यसमाज में सन्यासियों की खोड़ी में भी ऐसा ही माल मसाला पर्याप्त मात्रा में भरा रहता है, यह रहस्य सत्यार्थ-प्रकाश के चौथे समुल्लास की %पतिमेकादशं कृधि और नाक से नाक वाली कोकशास्त्रीय शिक्षाओं के देखने पर स्पष्ट हो जाता है।

क्यों कर्मानन्द जी! भला भविष्यपुराण में तो वेश्याओं की व्यभिचार वृत्ति छुड़ाने के लिये एक पुरुष के घर बैठ जाना भी आपको बेतरह अखरता है, परन्तु स्वामी दयानन्द का संसार भर की पतिव्रता स्त्रियों को बिना रोक टोक 11, 21 और अगणित पुरुषों से व्यभिचार करने का हुक्म आपको सूझता भी नहीं। यही क्यों (1) वहाँरी कन्याओं का विवाह से पूर्व ही गुप्त व्यवहार में ट्रेण्ड हो जाना (स0 प्र0 63) (2) विवाह संस्कार के पूर्व इमन्ते उपस्थं मन्त्र द्वारा वर के मूत्रेन्द्रिय पर शहद, शराब यण जल डालना (सं0 वि0 पृ0 126)। (3) पति की लाश घर में पड़ी रहते ही किसी महाशय से आर्यसमाज कराना (स0 प्र0 118) (4) सगर्भा होते हुये भी दूसरा गर्भ ठुसवाने की चेष्टा करना (स0 प्र0 123) आदि तुच्छ दयानन्दीय शिक्षाओं पर भी कभी ध्यान दिया है?

क्रमशः ...

रानी दुर्गावती बलिदान दिवस

इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कम संख्या नहीं हैं। लेकिन उनमें से केवल रानी दुर्गावती ऐसी हैं जिन्हें उनके बलिदान और वीरता के साथ गोंडवाना का एक कुशल शासक के तौर पर भी याद किया जाता है। 24 जून को देश उनका बलिदान दिवस मनाता है जब उन्हें मुगलों की आगे हार स्वीकार नहीं की और आखिरी दम तक मुगल सेना का सामना कर उसकी हसरतों को कभी पूरा नहीं होने दिया।

रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। वे कलिंजर के राजा कीर्तिसिंह चंदेल की एकमात्र संतान थीं। दुर्गावती के पति दलपत शाह का मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में रहने वाले गोंड वंशजों के 4 राज्यों, गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, में से गढ़मंडला पर अधिकार था। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती से विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपतशाह का निधन हो गया।

पति के निधन के समय समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था अतः रानी को स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभालना पड़ाय वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। रानी ने 16 साल तक इस क्षेत्र में शासन किया और एक कुशल प्रशासक की अपनी छवि निर्मित की। लेकिन उनके पराक्रम और शौर्य के चर्चे ज्यादा थे। कहा जाता है कि कभी उन्हें कहीं शेर के दिखने की खबर होती थी, वे तुरंत शस्त्र उठा कर चल देती थीं और और जब तक उसे मार नहीं लेती, पानी भी नहीं पीती थीं।

रानी दुर्गावती बेहद खूबसूरत भी थीं। जब मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खां ने रानी दुर्गावती के विरुद्ध अकबर को उकसाया था। अकबर अन्य राजपूत घरानों की विधवाओं की तरह दुर्गावती को भी रनिवासे की शोभा बनाना चाहता था। बताया जाता है कि अकबर ने उन्हें एक सोने का पिंजरा भेजकर कहा था कि रानियों को महल के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन दुर्गावती ने ऐसा जवाब दिया कि अकबर तिलमिला उठा।

रानी दुर्गावती ने मुगल शासकों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था और उनको अनेक बार पराजित किया था और हर बार उन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इंकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। दो हमलों के बाद 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला किया तब तक रानी की सैन्य शक्ति कम हो गई थी। ऐसे में रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया।

युद्ध के दौरान पहले एक तीर उनकी भुजा में लगा, रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया, रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आंख में ही रह गयी। इसके बाद तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। अंत समय निकट जानकर रानी ने वजीर आधारसिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गयीं। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है। मंडला रोड पर स्थित रानी की समाधि बनी है, जहां गोण्ड जनजाति के लोग अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

क्या ईरान-अमेरिका समझौता टिक पाएगा

साइमन मैबोन

ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, जिससे युद्धविराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाने और रणनीतिक रूप से अहम जलमार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन, कुछ अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं, जो इस समझौते को विफल कर सकते हैं।

वाशिंगटन और तेहरान के इस समझौते में लेबनान भी शामिल है। ईरान ने इस समझौते पर दस्तखत करने के लिए एक शर्त रखी थी कि इस्राइल उन इलाकों से पीछे हटने का वादा करे, जिन पर उसने युद्ध के दौरान दक्षिणी लेबनान में कब्जा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वह 'लेबनान में ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आएं।' लेकिन, समझौते के बाद दक्षिणी लेबनान और बेरूत पर इस्राइल की बमबारी जारी रही और लेबनान में इस्राइली सेना की मौजूदगी बनी हुई है। हालांकि, अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि इस्राइल और लेबनान के हिज्बुल्लाह के बीच युद्धविराम पर सहमति बन गई ?है। लेकिन, इस्राइली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि बेशक हम युद्धविराम की स्थिति में हैं, किंतु जरूरत पड़ी, तो लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार हैं।

समझौते के मुताबिक, लेबनान में इस्राइली सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। ईरान इस युद्ध में दोनों देशों को एक ही दुश्मन के तौर पर देखता रहा है। पिछले एक साल में, ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। इन सवालों से ईरान और पश्चिम एशिया के व्यापक सुरक्षा माहौल को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग नजरिये का पता चलता है। 2025 की गर्मियों में दोहा में हमास के ठिकानों पर इस्राइल के हमले के बाद ट्रंप ने नाराजगी भी जताई थी।

ईरान के साथ युद्ध के दौरान लीक हुई टिप्पणियों

से पता चलता है कि नेतन्याहू को लेकर ट्रंप कितने नाराज थे। 14 जून को अमेरिकी मीडिया आउटलेट 'एक्सियोस' से बात करते हुए ट्रंप गुस्से में बोले- 'बीबी (नेतन्याहू) को वह बकवास हमला करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत नाराज था। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि उनमें जरा भी समझदारी नहीं है। मैंने उन्हें यह बात बता दी।' बाद में ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर इस्राइल को चेतावनी दी कि 'सब कुछ बर्बाद न करें।'

दो हफ्ते पहले, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस्राइल की ओर से हवाई हमले फिर से शुरू करने की धमकियों को लेकर तीखी बातचीत हुई थी। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप चिल्लाए- 'तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। अगर मैं न होता, तो तुम जेल में होते। मैं ही तुम्हें बचा रहा हूं। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है। इसकी वजह से हर कोई इस्राइल से नफरत करता है।' ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तनाव, इस्राइल और अमेरिका के बीच उभरते बड़े रणनीतिक मतभेदों को भी दिखाता है। ये दोनों देश लंबे समय से करीबी राजनयिक सहयोगी रहे हैं और पश्चिम एशिया के भविष्य को लेकर उनकी रणनीतिक और वैचारिक सोच एक जैसी रही है। अमेरिका की घरेलू राजनीति और विदेश नीति, दोनों में ही इस्राइल का समर्थन एक अहम आधार रहा है, जिससे इस तरह के नजरिये के रणनीतिक फायदों पर बड़े पैमाने पर विचार-विमर्श हो रहा है।

अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी जॉन मीयरशाइमर और स्टीफन वॉल्ट के एक लेख (जो बाद में पुस्तक के रूप में छपी) में इस विषय पर चर्चा की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अमेरिका और इस्राइल के रिश्ते 'प्यार या लॉबी' का नतीजा हैं। इसमें 'अमेरिकन इस्राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी' द्वारा अमेरिकी नेताओं पर डाले जाने वाले दबाव का साफ जिक्र था, जिसे अमेरिका के सबसे ताकतवर लॉबिंग ग्रुप्स में से एक माना जाता है और अमेरिकी नीति पर जिसका काफी असर है। फिर भी, फिलहाल दोनों देशों के रणनीतिक लक्ष्य सीधे तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं।

अमेरिका के लिए यह सुनिश्चित करना सबसे जरूरी था कि ईरान के साथ समझौता हो जाए। वहीं इस्राइल में इस समझौते को हार जैसा माना जा रहा है और इससे लोगों में भारी गुस्सा है। वहां की आम जनता ईरान और हिज्बुल्लाह के साथ युद्ध के पक्ष में है। इस्राइल में कई लोग सरकार से इस समझौते को ठुकराने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के एक सदस्य, वित्त मंत्री इतामार बेन-ग्विर ने कहा कि इस्राइल को अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस्राइल को अमेरिका से दूर करने की कोशिश में, उन्होंने कहा कि 'एक संप्रभु देश किसी महाशक्ति का कठपुतली नहीं होता। वह ऐसे समझौतों से बंधा नहीं होता, जो उसके लोगों की सुरक्षा करने की उसकी क्षमता को रोकते हों।' उन्होंने तर्क दिया कि इस्राइल को 'दक्षिणी लेबनान में घर गिराने का काम जारी रखना चाहिए... हमें स्वतंत्र बने रहना चाहिए।' इस्राइल के रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने कसम खाई कि इस्राइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी और अगर ईरान लेबनान के समर्थन में इस्राइल पर हमला करता है, तो वह उसका जवाब देंगे। नेतन्याहू ने भी कड़ा रुख दिखाया। 15 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने 'इस्राइल के चारों ओर मजबूत सुरक्षा क्षेत्र बनाए हैं। हमने ऐसा गाजा, लेबनान और सीरिया में किया... और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए इन सुरक्षा क्षेत्रों में बने रहेंगे।'

ऐसा लगता है कि यह बात आपसी समझौते की शर्तों के बिल्कुल उलट है और इससे ट्रंप-नेतन्याहू तथा अमेरिका-इस्राइल के रिश्तों पर गंभीर सवाल उठते हैं। यह रिश्ता अब एक अहम मोड़ पर है। क्या ट्रंप लेबनान पर इस्राइली बमबारी रोकने और वहां से सेना हटाने का नेतन्याहू पर दबाव डालेंगे, या फिर वे इस्राइल की सैन्य कार्रवाई को नजरअंदाज करके समझौते को खतरे में डाल देंगे? अगर, अमेरिकी राष्ट्रपति इस्राइल से सेना हटाने की जिद करते हैं, तो क्या नेतन्याहू उनकी बात मानेंगे? और इसका दोनों नेताओं की चुनावी संभावनाओं पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू को अक्तूबर तक आम चुनाव का सामना करना है और ट्रंप को नवंबर की शुरुआत में मध्यावधि चुनावों का?

जब दो सहयोगी देश साफ तौर पर इस बात पर आमने-सामने हैं कि उनके देश (और शायद वे खुद) क्या चाहते हैं, तो क्या यह समझौता टिक पाएगा? और इसका इस्राइल और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? यह तो वक्त ही बताएगा।

आज का इतिहास

1793 फ्रांस ने पहली बार रिपब्लिकन संविधान को अपनाया।
1794 बाउडूइन कॉलेज की स्थापना ब्रंसविक, मेन में हुई।
1812 नेपोलियन के तहत नेपोलियन के युद्धों-फ्रांसीसी ग्रांडे आर्मे ने नेमन नदी पर रूस के अपने आक्रमण की शुरुआत को चिह्नित किया।
1812 नेपोलियन के युद्धों- नेपोलियन नदी के नीचे फ्रांसीसी ग्रांडे आर्मे ने रूस पर अपने आक्रमण की शुरुआत को चिह्नित किया।
1843 वीन्सेन्ज़ो सॉलिवा ने घोषणा किया की कोई यहूदी इटली में यहूदी बस्ती के बाहर नहीं रह सकता।
1859 फ्रांस और सारदेनिया के साथ ऑस्ट्रिया का सोल्फ़ोरीनो युद्ध हुआ।
1918 कनाडा में मॉन्ट्रियल से टोरंटो के बीच पहली एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई।
1922 अमेरिकन प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने नेशनल फुटबॉल लीग का नाम बदला।
1932 सैन्य और नागरिकों के एक समूह ने एक रक्तहीन कपिन सियाम का निर्माण किया, जिसने चकेरी राजवंश के पूर्ण शासन को समाप्त कर दिया।
1937 संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले दो तेज युद्धपोत, नॉर्थकैरोलीना वर्ग, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया नेवलशिपर्ड्स से आदेश दिए गए थे।
1948 विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली विश्व स्वास्थ्य परिषद जीनेवा में आयोजित की गई।
1963 डाक एवं टेलिग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरूआत की।
1981 हम्बर्गर ब्रिज खोला, ईस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर और इंग्लैंड में नॉर्थ लिंकनशायर को जोड़ने वाला, उस समय का सबसे लंबा-लंबा सस्पेंशन ब्रिज था।
1982 ब्रिटिश एयरवेज फ़्लाइट 9 ने इंडोनेशिया के माउंट गालुंगगंग के विस्फोट से ज्वालामुखीय राख के एक बादल में उड़ान भरी, जिससे इसके चारों इंजनों में खराबी आ गई।
1994 वॉशिंगटन के स्पोकेन काउंटी में एक संयुक्त राज्य वायु सेना बी-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस एयरफोर्स बेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसने चालक दल के चार सदस्यों को मार डाला, और बाद में सुरक्षा नियमों के अनुपालन के मामले पर एक केस स्टडी प्रदान की।
1995 दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व कप जीता।
2002 अफ्रीकी देश तंजानिया में ट्रेन दुर्घटना में 281 लोगों की मौत।
2004 मौत की सज़ा न्यूयॉर्क में असंवैधानिक घोषित कर दी गयी।

उत्तराखंड में नीतिगत निरंतरता और कड़े फैसलों का प्रभाव

जयसिंह रावत

उत्तराखंड जैसे भौगोलिक, सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य का नेतृत्व करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। राज्य गठन के बाद बीते 26 वर्षों में दस मुख्यमंत्री सत्ता में आए और सभी ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास की दिशा तय करने का प्रयास किया।

इनमें स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी का औद्योगिक और आधारभूत ढांचा विकास विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। किंतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल इस दृष्टि से अलग दिखाई देता है कि इसमें कई ऐसे निर्णय लिए गए, जिन्हें राजनीतिक जोखिम के कारण लंबे समय तक टाला जाता रहा था।

किसी भी सरकार का आकलन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उन नीतिगत फैसलों से किया जाना चाहिए जो राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक दिशा को प्रभावित करते हैं।

धामी सरकार की सबसे चर्चित और दूरगामी पहल देश की पहली समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करना रही है। इसकी संवैधानिक वैधता और व्यावहारिक पक्ष पर बहस जारी है, किंतु यह निर्विवाद है कि उत्तराखंड ने इस विषय पर राष्ट्रीय विमर्श का नेतृत्व किया।

विविध सामाजिक समूहों वाले राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे संवेदनशील विषयों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना आसान कार्य नहीं था। इस पहल ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति-प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया है और कई अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में रुचि दिखाई है।

युवाओं के भविष्य और प्रशासनिक विश्वसनीयता से जुड़ा नकल विरोधी कानून भी इसी श्रेणी का निर्णय माना जा सकता है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं ने लंबे समय तक युवाओं का विश्वास कमजोर किया था।

कठोर दंडात्मक प्रावधानों वाले इस कानून के बाद भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हुई है। हजारों पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से युवाओं में व्यवस्था के प्रति भरोसा पुनर्स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है।

महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि पहाड़ों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी माध्यम है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कृषि, जल-संरक्षण और पारिवारिक अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता और पलायन नियंत्रण में भी सहायता मिल सकती है।

कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दृढ़ता के संदर्भ में धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाना, अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध अभियान चलाना तथा माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई सरकार की एक स्पष्ट नीति के रूप में सामने आई है।

समर्थक इसे कानून के शासन की स्थापना मानते हैं, जबकि आलोचक इसके सामाजिक प्रभावों पर प्रश्न उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बहसें स्वाभाविक हैं, किंतु यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इन विषयों पर निर्णय लेने से परहेज नहीं किया।

धामी सरकार के कार्यकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि समान अवसर और स्थानीय हितों की रक्षा से जुड़ी है। राज्य आंदोलन की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सेवाओं में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और निवेश परियोजनाओं में स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। इससे राज्य आंदोलन के मूल उद्देश्यों को नई प्रासंगिकता मिली है।

आर्थिक मोर्चे पर यदि देखा जाए तो उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, चारधाम ऑल-वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, विस्तारित हेली सेवाएं तथा सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार राज्य की विकास रणनीति के प्रमुख घटक हैं। इन परियोजनाओं का प्रभाव केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कृषि उत्पादों के विपणन, आपदा प्रबंधन और रक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा।

निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने भी उत्तराखंड को राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर अधिक प्रमुखता से स्थापित किया। निवेश समझौतों को धरातल पर उतारना अभी चुनौती बना हुआ है, लेकिन औद्योगिक, पर्यटन, ऊर्जा और सेवा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं ने राज्य की आर्थिक आकांक्षाओं को नई गति दी है।

इसके साथ ही नई औद्योगिक नीतियों, स्टार्टअप प्रोत्साहन और पर्यटन आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रयास भी उल्लेखनीय हैं।

पर्यटन क्षेत्र में सरकार ने पारंपरिक धार्मिक पर्यटन से आगे बढ़कर विंटर टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, होम-स्टे मॉडल, सीमांत पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई है। यदि यह प्रयास दीर्घकाल तक जारी रहे तो पर्यटन का लाभ केवल कुछ शहरों तक सीमित न रहकर दूरस्थ गांवों तक पहुंच सकता है।हालांकि किसी भी संतुलित विश्लेषण में चुनौतियों की चर्चा आवश्यक है। उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी परीक्षा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की है।

हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते निर्माण कार्य, अनियंत्रित शहरीकरण, वनाग्नि, भू-धंसाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि विकास का मॉडल स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुरूप होना चाहिए। जोशीमठ जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि केवल परियोजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी पर्यावरणीय संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

दूसरी बड़ी चुनौती पलायन की है। सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के बावजूद दूरस्थ गांवों से जनसंख्या का बहिर्गमन पूरी तरह नहीं रुका है। इसके लिए स्थानीय रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति का वास्तविक परीक्षण तब होगा जब उसकी प्रभावशीलता सचिवालय से लेकर ब्लॉक और ग्राम स्तर तक दिखाई दे।

समग्र रूप से देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली ने उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। उनके कार्यकाल की विशेषता केवल योजनाओं की संख्या नहीं, बल्कि विवादास्पद और कठिन समझे जाने वाले विषयों पर निर्णय लेने की राजनीतिक इच्छा-शक्ति रही है।

नीतिगत साहस किसी भी सरकार की पहचान बन सकता है, किंतु उसकी अंतिम सफलता जनता के जीवन में दिखाई देने वाले बदलावों से ही मापी जाएगी।

आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान दौर के ये निर्णय उत्तराखंड को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर, प्रशासनिक रूप से अधिक सक्षम और सामाजिक रूप से अधिक संतुलित राज्य बनाने में कितने सफल सिद्ध होते हैं।

ईरान को अमरीका पर रणनीतिक बढ़त

अनीता इंदर सिंह

क्या अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच 17वीं सदी के फ्रांसीसी महल वर्साय में 17 जून को हस्ताक्षरित अमरीका-ईरान समझौता स्थायी शांति लाएगा? या फिर यह एक ऐसी शांति साबित होगा, जो दोनों देशों के बीच अगले युद्ध की तैयारी के लिए एक छोटी अवधि बनकर रह जाएगी? सबसे पहले, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि अमरीका और इसराईल ने मिलकर काम करते हुए भी न तो ईरान को हराया है और न ही वह सत्ता परिवर्तन हासिल कर पाए हैं, जिसके लिए वे निकले थे, हालांकि ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई 28 फरवरी को एक इसराईली हवाई हमले में मारे गए थे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमरीकी चिंताएं बनी हुई हैं लेकिन इसे समाप्त करने के लिए बातचीत की अवधि को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तेहरान को, हालांकि, बैलिस्टिक मिसाइलें रखने की 'अनुमति' दी जाएगी क्योंकि ट्रम्प का मानना है कि यदि सऊदी अरब और कतर सहित अन्य देशों के पास ये मिसाइलें हैं, तो पूरी निष्पक्षता के साथ ईरान के पास भी होनी चाहिएं। कुछ हद तक उल्लेखनीय रूप से, अमरीका ईरान को 'पुनर्निर्माण' के लिए 300 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करेगा और वाशिंगटन ईरान पर से 'सभी प्रकार के प्रतिबंधों' को समाप्त कर देगा। हॉर्मुज पर से नाकेबंदी हटाने और जलडमरूमध्य के माध्यम से मुक्त आवागमन को बहाल करने के बदले में तेहरान को अब आर्थिक राहत मिलेगी। हॉर्मुज में नौवहन को बंद करने की ईरान की क्षमता, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उसकी खुली वापसी के साथ, 4 महीने तक भारी बमबारी झेलने के बावजूद उसे पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के रूप में स्थापित करेगी। महीनों की तबाही और वैश्विक आर्थिक व्यवधान के बाद आया यह परिणाम, ट्रम्प के दोनों राष्ट्रपति कार्यकालों की सबसे बड़ी विदेश नीति विफलता को दर्शाता है, जिसके परिणाम पश्चिम एशिया में अमरीका की रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पहले से कहीं अधिक कठिन बना देंगे। पश्चिम एशियाई देश और अन्य देश भी इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अमरीका ईरान जैसे कमजोर देश के खिलाफ निर्णायक जीत हासिल करने में विफल रहा। वाशिंगटन ने खुद को अविश्वसनीय, अप्रत्याशित और सनकी भी दिखाया। इससे स्थिरता बनाए रखने की वाशिंगटन की क्षमता पर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को ठेस पहुंचेगी। इसराईली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर ट्रम्प ने युद्ध समाप्त करने और लेबनान पर हमले रोकने का दबाव डाला था। क्या इसकी कीमत उन्हें इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में हार के रूप में चुकानी पड़ेगी, यह एक खुला सवाल है। इसराईल ने इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर संसाधन झोंक दिए। उसके नागरिकों को ईरान से बार-बार बमों की धमकियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, नेतन्याहू ईरानी सत्ता परिवर्तन का अपना अंतिम लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। इस समझौते का अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ा है लेकिन सवाल यह है कि क्या वे कम से कम उस स्तर तक गिरेंगी, जो युद्ध शुरू होने से पहले था और वहां टिकी रहेंगी? इस बीच, ईरानी तेल की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। एक लेन-देन वाली कूटनीति पर चलने वाला भारत, जिसने ईरान पर हमला करने के दौरान अमरीका और इसराईल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की कभी निंदा नहीं की, जब तक मौका अच्छा है, उतना ईरानी तेल खरीदेगा जितना वह खरीद सकता है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देश ने ईरानी क्रांतिकारी शासन को वैधता प्रदान कर दी है, जबकि अमरीका के साथ दोनों के जुड़ाव के बावजूद पश्चिम एशियाई महाशक्ति के रूप में उभरने के इसराईल के सपने को चकनाचूर कर दिया है।

उपलब्धियां प्रचार की मोहताज नहीं

पी. चिदंबरम

9 जून, 2026 के आस-पास, कई अंग्रेजी और तमिल समाचार पत्रों में और संभवत: भारत के सभी अखबारों में एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें पिछले 12 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया गया था। यह कार्यकाल निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मोदी सरकार पहली बार 2014 में चुनी गई, फिर 2019 में दोबारा सत्ता में आई और 2024 में तीसरी बार चुनी गई। हालांकि तीसरी बार में पहले की तुलना में काफी कम सीटें मिलीं। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के कार्यकाल को किसी भी निर्वाचित प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल बताया। इस दावे को और प्रभावशाली बनाने के लिए इसकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से भी की गई, जबकि इस तुलना की जरूरत नहीं थी। बिना किसी तुलना के भी 12 वर्ष का कार्यकाल अपने आप में उल्लेखनीय है।

सभी जानते हैं कि नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनाव जीते और लगभग 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। अब तक वे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। हर सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने और थोड़ी-बहुत आत्मप्रशंसा करने का अधिकार होता है, लेकिन संबंधित विज्ञापनों में अपनी तारीफ सामान्य सीमा से कहीं आगे निकल गई। जनता ने दो वर्ष पहले ही मोदी सरकार के इन दावों को समझ लिया था और भाजपा को लोकसभा में केवल 240 सीटों तक सीमित कर दिया, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। इसके बावजूद, दो साल बाद वही दावे दोहराए जा रहे हैं। बिना किसी दुर्भावना के, मैं इन दावों में से तीन का उदाहरण देकर वास्तविकता बताना चाहता हूं।

सरकार की परिभाषा के अनुसार, 'लखपति दीदी' वह महिला है, जो किसी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की सदस्य हो। अगस्त 2025 में बताया गया था कि 1 करोड़ 48 लाख एसएचजी सदस्य 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। मार्च, 2026 में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा

गया कि 3 करोड़ 7 लाख 33 हजार 820 एसएचजी सदस्यों ने स्वयं को 'लखपति दीदी' घोषित किया है। यह सच है कि स्वयं सहायता समूहों का आंदोलन, जो मोदी सरकार से पहले शुरू हुआ था, महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायक रहा है। लेकिन यह दावा करना कि मोदी सरकार ने 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाई हैं, बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात लगती है। मुझे संदेह है कि किसी स्वतंत्र ऑडिट ने इस दावे की पुष्टि की है। इस दावे की थोड़ी और गहराई में जाते हैं। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की संख्या लगभग 53 करोड़ है। इनमें श्रमबल भागीदारी दर 41.7 प्रतिशत है, यानी लगभग 22 करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं या काम की तलाश में हैं। यदि 3 करोड़ 'लखपति दीदी' का दावा सही मान लिया जाए, तो इसका अर्थ होगा कि देश की कामकाजी या काम खोज रही हर सात महिलाओं में से एक 'लखपति' है। वहीं, एसएचजी सदस्यों की कुल संख्या लगभग 9-10 करोड़ मानी जाती है। इसका मतलब होगा कि स्वयं सहायता समूहों की हर तीन महिलाओं में से एक 'लखपति' है। असलियत यह है कि यह दावा महिला की व्यक्तिगत संपत्ति (नेट वर्थ) से संबंधित नहीं है, बल्कि उसके परिवार की वार्षिक आय से जुड़ा है। दावे में यह तथ्य छिपा लिया जाता है कि परिवार के अन्य सदस्य भी कमाई करते हो सकते हैं, परिवार की कुल वार्षिक आय पहले से ही एक लाख रुपये या उससे अधिक हो सकती है और संबंधित महिला का योगदान उस आय का केवल एक हिस्सा हो सकता है। वास्तव में, एक लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय भारत जैसे देश में कोई असाधारण या दुर्लभ बात नहीं है। '3 करोड़ लखपति दीदी% का दावा सुनने में जितना प्रभावशाली लगता है, उसके पीछे की वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल और सीमित है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का दावा खोखला है।

एक नजर हवाई अड्डों के पहलू पर डालते हैं। देश में हर साल बुनियादी ढांचे का विकास होता है और इसमें हवाई अड्डों का निर्माण भी शामिल है। हवाई अड्डे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व वाले, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित अथवा पूरी तरह निजी हो सकते हैं। सरकार का 164 हवाई अड्डों का आंकड़ा सही हो सकता है, लेकिन यहां महत्वपूर्ण शब्द है ऑपरेशनल। सामान्य नागरिक यह समझेगा कि ऑपरेशनल हवाई अड्डे का मतलब ऐसा हवाई अड्डा है, जहां नियमित रूप से वाणिज्यिक यात्री उड़ानें संचालित होती हैं। यदि इसी कसौटी पर दावे को परखा जाए, तो सरकार का दावा पूरी तरह सही नहीं ठहरता। कई हवाई अड्डे रक्षा सेवाओं, माल ढुलाई (कार्गो) या प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े हैं, लेकिन वहां से नियमित यात्री उड़ानें संचालित नहीं होतीं। उड़ान योजना के अंतर्गत अनेक छोटे हवाई अड्डों को चालू किया गया और यात्री सेवाएं शुरू करने का प्रयास किया गया। इस योजना के तहत 774 मार्ग एयरलाइनों को आवंटित किए गए, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार 403 मार्गों पर कभी भी वाणिज्यिक सेवाएं शुरू ही नहीं हुई। सीएजी ने यह भी पाया कि केवल 112 मार्ग ही तीन वर्ष की सब्सिडी अवधि तक संचालित हो पाए। सब्सिडी समाप्त होने के बाद इनमें से मात्र 54 मार्ग ही संचालित हैं। वर्ष 2025 में स्वयं सरकार ने स्वीकार किया कि उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित 15 हवाई अड्डे फिर से गैर-परिचालन (नॉन-ऑपरेशनल) हो गए। जन औषधि केंद्र योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन 2013 तक यह लगभग असफल साबित हुई। इसके बाद 'सरकार का काम व्यापार करना नहीं है' की नीति के बावजूद मोदी सरकार ने 2015 में इस योजना का पुनर्गठन किया और इसे फ्रेंचाइजी मॉडल पर दोबारा शुरू किया, ताकि लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

पुतिन के गढ़ में घुसकर हमले कर रहा यूक्रेन, दुनिया हैरान

नीरज कुमार दुबे

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन ने न केवल रूस के सीमावर्ती इलाकों बल्कि राजधानी मॉस्को के भीतर तक अपनी पहुंच साबित कर दी है। जिस क्रेमलिन से राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन पूरे रूस का शासन चलाते हैं, उसके आसपास तक ड्रोन हमलों की गूंज सुनाई देने लगी है। साथ ही मॉस्को पर हुए बड़े ड्रोन हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध अब केवल मोर्चों पर नहीं बल्कि रूस के दिल तक पहुंच चुका है।

रूसी अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन की ओर से भेजे गए उनसठ ड्रोन राजधानी की तरफ बढ़ रहे थे जिन्हें रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया। हालात इतने गंभीर हो गए कि मॉस्को के चारों प्रमुख हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। विमानन विभाग ने कहा कि यात्रियों और उड़ानों की सुरक्षा के लिए यह कदम जरूरी था। राजधानी के लोगों ने रातभर धमाकों की आवाजें सुनीं और कई इलाकों में भय का माहौल बन गया। रूस के लिए यह केवल सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन अब सीधे उस सत्ता केंद्र तक खतरा पैदा कर रहा है जहां से पुतिन युद्ध संचालन कर रहे हैं। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस की ऊर्जा व्यवस्था को भी निशाना बनाया है। मॉस्को और अन्य शहरों की तेल रिफाइनरियों पर लगातार हमले किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण कई तेल संयंत्रों का कामकाज प्रभावित हुआ और कुछ स्थानों पर ईंधन आपूर्ति बाधित हो गई। अमेरिकी ऊर्जा अनुसंधान संस्थाओं के अनुसार रूस की लगभग एक तिहाई तेल शोधन क्षमता पर असर पड़ा है। रूस जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश में पेट्रोल की कमी दिखाई देना अपने आप में असाधारण स्थिति मानी जा रही है। कुछ इलाकों में पेट्रोल की बिक्री सीमित करनी पड़ी जबकि ईंधन निर्यात पहले ही रोका जा चुका है।

सबसे गंभीर स्थिति रूस के कब्जे वाले क्रीमिया क्षेत्र में दिखाई दे रही है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कर्च शहर के तेल भंडार और क्रास्नोदार क्षेत्र के ईंधन परिवहन केंद्रों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की खबर है। क्रीमिया प्रशासन ने

आम नागरिकों को पेट्रोल बिक्री रोक दी है और केवल सरकारी सेवाओं को ही ईंधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पेट्रोल के लिए परेशान नजर आ रहे हैं जबकि कुछ लोग बाजार कीमत से दोगुने दाम पर ईंधन बेचते दिखे।

उधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इन कार्रवाइयों को रूस की ऊर्जा व्यवस्था के खिलाफ लंबी दूरी की रणनीतिक कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि रूस केवल ताकत की भाषा समझता है और यूक्रेन अब वही भाषा इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है, क्योंकि तेल और ईंधन से होने वाली कमाई का इस्तेमाल रूस युद्ध संचालन में कर रहा है।

इसके अलावा, जहां एक ओर यूक्रेन रूस के भीतर गहरे हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। डोनबास क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर कोस्त्यांतिनिवका इस समय युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यूक्रेनी सैनिकों के अनुसार रूसी सैनिक शहर के भीतर तक घुस चुके हैं और अब उसे चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यह शहर रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद रूस के लिए क्रामातोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगी।

यूक्रेनी ड्रोन संचालकों का कहना है कि शहर अब लगभग धुंधले नियंत्रण क्षेत्र में बदल गया है जहां किसी एक पक्ष का पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। रूसी सैनिक इमारतों और पेड़ों का सहारा लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों और सैनिकों की कमी है। कई सैनिकों ने स्वीकार किया कि उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही और रूसी सेना लगातार दबाव बना रही है।

देखा जाये तो रूस की रणनीति अब केवल सीधे हमले तक सीमित नहीं है। रूसी ड्रोन इकाइयां यूक्रेनी ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को नष्ट करने पर विशेष ध्यान दे रही हैं ताकि यूक्रेन की निगरानी और जवाबी कार्रवाई कमजोर हो सके। यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि यदि उन्होंने अपनी रणनीति नहीं बदली तो रूस धीरे-धीरे और इलाकों पर कब्जा करता जाएगा।

उधर, युद्ध का असर केवल सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक संबंधों पर भी दिखाई दे रहा है। पोलैंड और यूक्रेन के बीच दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पोलैंड के राष्ट्रपति कारोळ नावरोत्स्की ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से देश का सर्वोच्च सम्मान वापस ले लिया है। इसके विरोध में यूक्रेन के कई पूर्व राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने पोलिश सम्मान लौटा दिए। दरअसल, विवाद उस यूक्रेनी सैन्य इकाई के नाम को लेकर है जिसे ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के नाम पर रखा गया जिस पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलिश नागरिकों के नरसंहार का आरोप है।

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस टकराव को दोनों देशों के लिए खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि ऐसे विवाद व्यापार, भू राजनीति और दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन और पोलैंड मित्र बने रहेंगे और दोनों देशों के बीच टकराव केवल रूस को फायदा पहुंचाएगा।

बहरहाल, इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब केवल सीमावर्ती संघर्ष नहीं रह गया है। यूक्रेन ने मॉस्को तक पहुंच कर रूस को चौंका दिया है, जबकि रूस पूर्वी यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान को और तेज कर रहा है। ऊर्जा संकट, ड्रोन युद्ध, राजनीतिक तनाव और नागरिकों की बढ़ती परेशानियां इस संघर्ष को और अधिक जटिल बना रही हैं इसलिए अब केवल रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस युद्ध के अंत का इंतजार कर रही है। हालांकि मौजूदा हालात देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन और जेलेंस्की, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

दलबदल विरोधी कानून में गंभीर खामियां

कल्याणी शंकर

भारतीय विपक्ष अपनी पार्टियों के भीतर चल रहे संघर्षों के कारण काफी राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह जटिल राजनीतिक परिदृश्य, जहां पार्टी बदलना और दलबदल आम हो गया है, स्वाभाविक रूप से कई लोगों के लिए इक्षचताजनक है। ऐसी कार्रवाइयां विश्वास को कम व जवाबदेही को कमजोर कर सकती हैं और हमारी लोकतांत्रिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। इन अनिश्चित समयों के दौरान हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी महसूस करना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य राजनीतिक विभाजन का अनुभव कर रहे हैं। संसद सदस्यों को लुभाने के लिए खरीद-फरोख्त के दावे किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यू.बी.टी.) बढ़ते दबाव का सामना कर रही है। शिवसेना (यू.बी.टी.) के भीतर महत्वपूर्ण दरारें एक बार फिर गहरी हो गई हैं। खबरों के अनुसार, शिवसेना (यू.बी.टी.) के लगभग 16 विधायक और 7 सांसद एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सदस्य पहले ही भाजपा का दामन थाम चुके हैं। पंजाब में स्थिति 'आप' के लिए अच्छी नहीं है। बंगाल में, जहां अभी भाजपा ने अपनी पहली सरकार बनाई है, 20 टी.एम.सी. सांसद त्रिपुरा के एक कम ज्ञात राजनीतिक समूह में शामिल हो रहे हैं। वे ऐसा दलबदल विरोधी कानून से बचने के लिए कर रहे हो सकते हैं। बागी समूह ने लोकसभा अध्यक्ष से संसद में अलग बैठने की मांग की है। इस बीच, मूल पार्टी के वफादार सदस्यों का तर्क है कि एक उचित विलय में पूरी पार्टी शामिल होनी चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत विधायक। इसके अतिरिक्त, भाजपा के सहयोगी ओ.पी. राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी जल्द ही विभाजित हो सकती है लेकिन सपा नेतृत्व इसका पुरजोर खंडन करता है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक को भी आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा के नेतृत्व वाला एन.डी.ए. छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को आकर्षित करके लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए काम कर रहा है। वर्तमान में उनके पास 293 सीटें हैं और वे तृणमूल कांग्रेस के बागियों के समर्थन से इसे बढ़ाने का लक्ष्य बना रहे हैं। यदि दमुक उनके साथ जुड़ती है, तो गठबंधन अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकता है। ये आंतरिक संघर्ष और बाहरी राजनीतिक रणनीतियां सवाल उठाती हैं कि क्या पार्टी की अस्थिरता बाहरी प्रभावों से पैदा हो रही है या आंतरिक नेतृत्व के मुद्दों से? संसद में विपक्ष की ताकत 2022 में शिवसेना और 2023 में राकांपा के विभाजन के बाद से सबसे ज्यादा बदल रही है, दलबदल लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जवाबदेही और सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। दलबदल विरोधी कानून की वर्षों से लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू को कमजोर करने के लिए तीखी आलोचना की गई है-निर्वाचित विधायकों की शक्ति। प्रभावी रूप से, यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों पर पार्टियों को सशक्त बनाता है। लेकिन यह कानून दलबदल को रोकने के अपने घोषित उद्देश्य को हासिल करने में असमर्थ रहा है। जब से यह अधिनियमित हुआ है, दलबदल निर्बाध रूप से जारी है। जैसा कि हम तृणमूल के मामले में देख सकते हैं। इसने बस इतना किया है कि दलबदल को एक थोक का खेल बना दिया है। इन बदलावों को पहचानना इस बात को रेखांकित करता है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है। दलबदल के प्रभाव को समझना मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा और सुधारों की वकालत करने में अपनी भूमिका देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। इन बदलावों के परिणाम काफी हैं, जो विधायी प्रक्रियाओं और मतदाता विश्वास को प्रभावित कर रहे हैं। इन बदलावों के कारण विविध और जटिल हैं, जिनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और मौजूदा पार्टी विचारधाराओं से असंतोष शामिल है। राजनेता अक्सर उन पार्टियों के साथ नए अवसर तलाशते हैं, जो अधिक आकर्षक पद प्रदान करती हैं।

इस सीजन के रग्ज...

अपने घर के लिए इस सीजन में रग्ज खरीदने से पूर्व उसके फाइबर, रंगों के बारे में अच्छी तरह जांच-परख लें। खासकर बरसात के मौसम में चटख रंग न खरीदें। अपने कमरे के फर्श को रग्ज से सजाने से पहले कमरे का साइज और डाइमेंशन पर गौर करें कि कहां-कहां रग्ज थोड़ा और कहां इसका फैलाव ज्यादा आएगा। जैसे दरवाजों के पास रग्ज को थोड़ा काटना पड़ सकता है। अगर आप अपने कमरे को रग्ज से कवर करना चाहते हैं तो यह आपके कमरे की दीवार से दो फीट छोटा होना चाहिए। कई वाल टू वाल रग्ज लगाना भी पसंद करते हैं। रग्ज सुंदर दिखे यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी बुनावट किस तरह की गई है? इसकी फिनिशिंग कैसी है? सवाल यह नहीं कि जो भी रग्ज आप खरीदने जा रहे हैं, वह कितना महंगा है? और वह सबसे बढ़िया है कि नहीं? सवाल यह है कि रग्ज वही बढ़िया है, जो आपके घर में सजता है। प्लांट बेस्ड फाइबर जैसे जूट, हेम्प आदि ऐसे रग्ज हैं जो किसी भी स्पेस में आसानी से फिट हो सकते हैं। ये अलग-अलग स्टाइल में मौजूद हैं और आपके घर के डेकोर के साथ आसानी से मैच कर सकते हैं। नेचुरल फेब्रिक सदाबहार हैं। इन्हें पारम्परिक, आधुनिक या फिर ग्रामीण परिवेश वाले घर और बीच हाऊस में सजाया जा सकता है। इनका जमीनी टेक्सचर काफी आकर्षक है। ये रग्ज सुनहरी तथा सिल्की शाइन में भी होते हैं। लोककला आधारित फेब्रिक तथा फ्लोरल आर्ट के साथ-साथ ट्रॉपिकल लैंडस्केप हमें इन गर्मियों में भी कूल-कूल अहसास देती है।

मच्छरों को भगाने वाला टीवी...

टीवी घर में मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है और अगर यह टीवी आपके मनोरंजन के साथ-साथ मच्छरों की समस्या से भी निजात दी लाए तो फिर क्या कहने। जी हां, अब आपको मच्छर भागने के लिए किसी मॉस्किटो कोल नहीं बस टीवी ऑन कीजिए और मच्छर दूर भाग जाएंगे। एलजी ने एक ऐसा ही टीवी लॉन्च किया है जो मनोरंजन के साथ-साथ मच्छर दूर करने का भी काम करता है। मॉस्किटो अवे टीवीकी शुरुआती कीमत भारतीय बाजार में 26,900 रुपए तय की है जो 47,500 रुपए तक है। एलजी मॉस्किटो अवे टीवी भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर विकसित गया है। इसमें अल्ट्रा सोनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है जो एक बार एक्टिवेट होने के बाद मच्छरों को दूर भागाने का काम करती है। इसमें साउंड वेब्ज तकनीक के जरिए यह बिना किसी हानिकारक रेडिएशन के मच्छरों को दूर करती है। कंपनी का दावा है कि यह तकनीक वैश्विक संगठनों के नियमों के अनुरूप है। इसकी जांच भारत के अंतरराष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी एवं विषज्ञान संस्थान में भी की गई है। इस मच्छर भगाने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए टीवी को हमेशा चालू रखने की भी जरूरत नहीं है।

चेहरे और शरीर का ध्यान रखें...

आमतौर पर लड़के अपने चेहरे और शरीर के रखरखाव को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं होते हैं, लेकिन आज के समय में लोगों का चेहरा भी उन्हें सफलता दिलाने का काम करता है। ऐसे में युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। चेहरे पर साबुन लगाने से नमी चली जाती है। फेशवॉश का इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पर मुंहासें है तो उनका उपचार करें। उन्हें फोड़ें नहीं और न ही उन पर साबुन लगाएं। कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। क्लीन शेव लड़के हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन कई लड़कों को दाढ़ी रखना पसंद होता है चाहे बाल हो या नहीं। ऐसे में चेहरे पर कुछ जगह दाढ़ी और कुछ जगह खाली हिस्सा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। दाढ़ी के साथ एक्सपेरिमेंट न करें और हमेशा क्लीन शेव बने रहें। साथ ही जब शेव करें तो गर्दन के बाल भी ट्रिम कर लें। ये शर्ट पहनने पर बहुत भद्दे दिखते है। युवाओं की नाक के बाल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ऐसे में नाक के बाल काट लें। इससे सामने वाले को आप से घिन नहीं आएगी। इसके अलावा कई युवाओं को पीठ में छोटे-छोटे पस भरे दाने होते हैं, इनका उपचार करें। सही साबुन का इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर डर्मेटोलॉजिस्ट से सम्पर्क करें।

तेजी से कैसे बढ़ाएं दाढ़ी...?

कुछ ऐसे तरीके हैं, जिसे अपनाकर आप दाढ़ी की वृद्धि दर को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी ठीक ढंग से देखभाल करनी होगी। त्वचा के लिए तैयार कोई अच्छा एक्सफोलिएट मास्क भी ट्राइ करें। इससे दाढ़ी के बालों को उगने में मदद मिलेगी। धैर्य रखें और अपनी दाढ़ी को बढ़ने और विकसित होने दें। विकसित हेने के बाद खाली जगह अपने आप ही भरने लगेंगी। प्रोटीन शरीर को ऐसे पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराता है जो ज्यादा बालों को उगाता है और सोना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी समय पौष्टिक तत्व अपना काम करता है। कैस्टर के तेल को एक बेहतरीन कंडीशनिंग ट्रीटमेंट माना जाता है, जो बालों को बढ़ाने के साथ-साथ आपकी दाढ़ी को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। विटामिन बी1, बी6 और बी12 भी बालों को जल्दी बढ़ाने में मदद करता है।

हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित किन्नौर जिले को हाल ही में देशभर के प्रथम वायु-प्रदूषण मुक्त जिले का खिताब मिला है। किन्नौर को प्रकृति ने दिल खोलकर सुंदरता नवाजी है। वैसे किन्नौर की जीवनशैली अब रॉयल हो चली है। जिले के हर घर में कम से कम एक गाड़ी जरूर है और किन्नौर के सभी गांवों में अब 80 प्रतिशत तक घर पक्के बन चुके हैं। पहले ये घर मिट्टी, पत्थर व लकड़ी के हुआ करते थे। वायु-प्रदूषण से मुक्त होने के साथ ही किन्नौर कई मामलों में खास है। किन्नौर में और क्या रहस्य हैं यही जानने की कोशिश है यह आलेख।

रुपसियों का देश...

हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित किन्नौर जिले को हाल ही में देशभर के प्रथम वायु-प्रदूषण मुक्त जिले का खिताब मिला है। किन्नौर की हवा को लेकर रिसर्च में पाया गया कि हिमाचल के इस खूबसूरत जनजातीय जिला में 2.5 माइक्रोन के पीएम यानी पार्टीकुलेट मैटर का स्तर सालाना 3.7 जमा माइनस वन प्रति क्यूबिक मीटर पाया गया।

यह नेशनल एयर क्वालिटी टारगेट से दस फीसदी कम है। दिल्ली की भयावह स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां यह स्तर 148 जमा माइनस 51 प्रति क्यूबिक मीटर है। यदि हवा साफ हो और तय मानकों के अनुसार हो तो भारत में हर साल 45 हजार लोग दूषित हवा के कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों से मरने से बच सकते हैं। दूषित शहरों में लोगों की जीवनी शक्ति भी कम हो जाती है। लेकिन किन्नौर का जीवन खुली किताब है और अनेक रहस्यों को समेटे भी। यहां के रीति-रिवाज आपको चौकाएंगे भी, लुभाएंगे भी। कुदरत भी यहां अपने हर रूप में मौजूद है, सुरम्य भी और खतरनाक भी।

आसमां से ऊंचे हिमशिखर, बर्फीले झरने, गुनगुनाती बलखाती नदियां-ये नजारे नयनाभिराम हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के बाद जब यह इलाका कुछ माह के लिए शेष दुनिया से कट-छट जाता है, तब कुदरत के कठोर थपेड़ों का एहसास करवाता है किन्नौर। हमारे पुरातन ग्रंथों में किन्नरी शब्द का संबोधन रूपसी के लिए किया गया है। शायद उसी किन्नर शब्द से ही यह किन्नौर बसा है। यानी रुपसियों का देश लेकिन हालिया वर्षों में किन्नर शब्द का प्रयोग देशभर में ट्रांसजेंडर के लिए किया जाने लगा है जिससे वहां के लोग खासे दुखी हैं। इसे लेकर समय-समय पर उन्होंने सरकार को ज्ञापन भी सौंपे हैं। कुदरत की तरह ही हिमाचल के इस कबाइली इलाके की महिलाओं का सौंदर्य भी नैसर्गिक है यानी ऐसी खूबसूरती जो मेकअप की लीपापोती की मोहताज नहीं। यहां की युवतियविशुद्ध देसी, लेकिन लावण्य से भरपूर ं मेकअप से कोसों दूर हैं।

कुदरत ने जो हुस्न बख्शा है, उसकी चमक बरकरार रखने के लिए उन्हें किसी तरह की लीपापोती की जरुरत नहीं। कच्चे अखरोट की दातुन से चिट्टे-चिट्टे दांत और उसी से होंठों की लाली का देसी मेकअप कोई इनसे सीखे। इन पर अभी तक जमाने का रंग कम ही चढ़ पाया है। हालांकि कई इलाकों में किन्नौरी परिधानों के इतर जीन्स व सलवारें पहने किशोरियां दिख जाती हैं लेकिन अधिकांश पारंपरिक वेशभूषा में ही नजर आती हैं।

आदर-सत्कार की भावना

यहां के प्राकृतिक सौंदर्य की तरह यहां के लोग भी सुंदर हैं। किन्नर बालाएं फलों से सुसज्जित अपनी परंपरागत टोपियां पहनती हैं। टोपियों के दोनों ओर पीपल पत्र नामक चांदी का एक गहना बना होता है और चांदी के ही एक नक्काशीदार कड़े पर कसा रहता है। अपने शरीर को ये ऊनी कम्बल से साड़ी की भांति लपेटे रखती हैं। इस ऊनी कम्बल को स्थानीय भाषा में 'दोहडू' कहा जाता है।

किन्नरियों में मेहमानों के आदर-सत्कार की भावना भी बहुत होती है। मेहमानों का स्वागत वे अपने हाथों से शराब पेश करके करती हैं। ऐसा करते समय उन्हें कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि शराब को किन्नर समाज में महत्व प्राप्त है, लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि जहां किन्नरियां शराब को बनाने से लेकर पेश करने तक का कार्य अपने हाथों से करती हैं, वहीं वे स्वयं शराब को मुंह तक नहीं लगातीं। शाल बुनने में तो उनका कोई सानी नहीं है। उनकी बनाई शालों में प्रकृति के विभिन्न रूप परिलक्षित होते हैं। सर्दियों में जब भारी बर्फबारी के कारण किन्नौर का सम्पर्क शेष दुनिया से कट जाता है तो किन्नारियां ऊनी कपडे, कालीन और अन्य चीजें बुनने का काम करती हैं। उनके बनाए ऊनी वस्त्रों में डोहरियां, पट्टू, गुदमा आदि उल्लेखनीय हैं।

जूठी घास नहीं खाता याक

प्राकृतिक नजारों से भरपूर किन्नौर के लोग बड़ी संख्या में भेड़-बकरी पालन का काम करते हैं। यहां तक कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तक में कार्यरत अधिकारियों के परिवारों में भी अभी तक भेड़-बकरी पालन की परंपरा जारी है। कन्नौर क्षेत्र में कहीं-कहीं याक पाया जाता है। यह जानवर पालतू व जंगली दोनों तरह का होता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि अन्य अपवित्र पदार्थो की तो बात ही छोड़िए, दूसरे जानवरों द्वारा चरी हुई घास को भी यह जूठा मान कर छोड़ देता है और नई उगी घास ही खाता है। याक में सूंघने की विलक्षण शक्ति ोती है। बर्फ के नीचे छिपे गढ्ढों का इसे पता चल जाता है और यह उनसे बच कर ठीक मार्ग बनाता हुआ आगे बढ़ता चलता है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में कई जगह गहरे गड्ढ़ों में गिरने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। याक की सूंघने की क्षमता का लाभ मनुष्य को भी मिलता है। इसे नमक बहुत पसंद है। किसी पत्थर पर नमक लगाकर इसके आगे रख दिया जाए तो याक उसे कई घंटों तक चाटता रहता है। वैसे तो यह सीधा-सादा जानवर है, परंतु किसी कारण इसे क्रोध आ जाए तो खैर नहीं। प्राय: किन्नौर के याक का रंग सफेद होता है। दूसरे रंग का याक सुगमता से दिखाई नहीं देता। किन्नौर की वादियों का आकर्षण देश-विदेश से यहां आए सैलानियों के हृदय में ऐसा समा जाता है कि वे यहां की नैसर्गिक सुंदरता तथा धार्मिक आस्था वाले भोले-भाले लोगों से हुई अपनी मुलाकात को लंबे समय तक अपने दिल में संजोए रहते हैं। यही नहीं, हिमालय की रचना के गूढ़ रहस्यों को जानने की चेष्टा करते हुए जिज्ञासु पर्यटक बार-बार यहां आने की इच्छा मन में संजोए रहते हैं।

विज्ञान की मुहर लगी

अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए दशकों से प्रसिद्ध रहा है किन्नौर लेकिन अब देश का पहला वायु प्रदूषणमुक्त जला घोषित होने के बाद वैज्ञानिक तौर पर भी यहां की जलवायु पर मोहर लग गई है। किन्नौर प्राकृतिक नजारों से न केवल लबरेज है, बल्कि यहां की मनोरम घाटियां और चट्टानें काटकर बनाई गई सड़कें यहां घूमने आने वालों को रोमांच का अनुभव करवाती हैं। यहां के महाभारत काल के अधिकांश देवालय विदेशी पर्यटकों समेत सभी को मंत्रमुग्ध करते हैं। शीत मरुस्थल के रूप में विख्यात किन्नौर अब साल भर लोगों की पहुंच के भीतर रहता है। हालांकि गर्मियों में यहां आना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सर्दियों में यहां अधिकांश स्थानों पर तापमान जमाव बिंदू से नीचे रहता है। इसके अलावा बर्फबारी भी अक्सर सर्दियों में किन्नौर का रास्ता रोक देती है। एक ओर यह तिब्बत से सटा है, वहीं दूसरी ओर इसकी सीमाएं लाहौल स्पिति और शिमला को भी छूती हैं। पर्यटन की बयार किन्नौर तक पहुंच चुकी है। सांगला और रिकांगपिओ वैली में अब विश्वस्तरीय होटल बन चुके हैं, जो अक्सर विदेशी सैलानियों से भरे रहते हैं। सांगला घाटी में पिछले कुछ सालों के दौरान होम स्टे ने भी काफी जोर पकड़ा है और लोगों ने अपने घरों को होम स्टे के तहत होटलों में तबदील कर दिया है।

बहु पति विवाह

किन्नौर क्षेत्र की लड़की का विवाह एक ही परिवार के सभी सगे भाइयों से एक साथ किया जाता है। यहां के निवासी इस प्रथा का संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ते हैं। घर की एक ही छत के नीचे रहने वाले परिवार के सभी भाई एक ही युवती से परंपरा के अनुसार शादी करते हैं और विवाहित जीवन जीते हैं। अगर किसी महिला के कई पतियों में से किसी एक की मौत भी हो जाए तो भी महिला को दु:ख नहीं मनाने दिया जाता है। किन्नौर में विवाह की परंपरा भी अजीब ढंग से निभाई जाती है। जब किसी युवती की शादी होती है तो परिवार वाले उस परिवार के लड़कों के बारे में पूरी जानकारी आदि ले लेते हैं। विवाह में सभी भाई दूल्हे के रूप में सम्मलित होते हैं। शादी के बाद निभाई जाने वाली कई परंपराएं और बाद का विवाहित जीवन एक टोपी पर निर्भर करता है। जैसे किसी परिवार में चार भाई है। सभी की विवाह एक ही महिला से हुआ है। अगर कोई भाई अपनी पत्नी के साथ है तो वह कमरे दरबाजे पर अपनी टोपी रख देता है। भाइयों में मान मर्यादा इतनी रहती है कि जब तक टोपी दरवाजे पर रखी है कोई दूसरा भाई उस स्थान पर नहीं जा सकता। जनजातीय जिला किन्नौर में भोटी भाषा प्रचलित है। बोलचाल की भोट भाषा में किन्नौर को खुनु, बुशैहरी और स्थानीय लोग कन्नावर या कनौर कहते हैं। स्थानीय भाषा में लोग अपने को कनौरस या किन्नौरस कहते हैं। तिब्बती लोग किन्नौरों को खुनु-पा कहते हैं और किन्नौरे अपनी भाषा को कनौवरिंगकत कहते हैं। किन्नौर में एक ही किन्नौरी भाषा अथवा कनौवरिंगकत ही नहीं है, बल्कि हर गांव में अलग-अलग बोलियां बोली जाती हैं। फिर भी इस अनेकता को एकता के रूप में बांधने वाली एक किन्नौरी भाषा को पूरे किन्नौर में प्रयोग कर सकते हैं।

महिला होती है मुखिया

यहां पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं घर की मुखिया होती हैं। इनका काम होता है पति व संतानों की सही ढंग से देखभाल करना। परिवार की सबसे बड़ी स्त्री को गोयने कहा जाता है। उसके सबसे बडे पति को गोर्तेस, कहते हैं यानी घर का स्वामी। यहां की एक और बात खास होती है वह यह कि यहां खाने के साथ शराब अनिवार्य होती है। यदि पुरुषों का मन दुखी होता है तो यह शराब और तम्बाकू का सेवन करते हैं वहीं जब महिलाओं को किसी बात को लेकर दु:ख होता है तो वह गीत गाती हैं। सर्दी में बर्फबारी की वजह से यहां की महिलाएं और पुरुष घर में ही रहते हैं। बर्फबारी की वजह से कोई काम नहीं रहता है। इन दिनों इन लोगों के पास बस मौज मस्ती में दिन व रात गुजारने होते हैं। महिलाएं सारा दिन पुरुषों के साथ गप्पें मारती हैं। किन्नौर जिले का मुख्यालय रिकांग पिओ है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों और हरे-भरे पेड़ों से घिरा यह क्षेत्र ऊपरी, मध्य और निचले किन्नौर के भागों में बंटा हुआ है। यहां पहुंचने का मार्ग दुर्गम होने के कारण यह क्षेत्र बहुत लंबे समय तक पर्यटकों से अछूता रहा है, लेकिन अब साहसिक और रोमांचप्रिय पर्यटक यहां बडी संख्या में आने लगे हैं। प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत से सटी हुई है, जो इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 250 किमी. दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर यह नगर स्थित है। पहाड़ों और जंगलों के बीच कलकल ध्वनि से बहती सतलुज और स्पीति नदियों का संगीत यहां की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। स्पीति नदी आगे चलकर खाब में सतलुज से मिल जाती है।

अंधेरे में इस्तेमाल न करें स्मार्टफोन...

आप भी उन लोगों में जरूर शामिल होंगे जो रात को सोने से पहले कमरे की लाइट बुझाकर अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आप अभी तक ऐसा करते आए हैं तो अब आपको संभल जाने की जरुरत है। बता दें कि लगातार ऐसा करने के चलते कई लोगों में अंधेपन के लक्षण देखें गए हैं और दो महिलाएं तो पूरी तरह आंखों की रौशनी गंवा बैठी हैं।

कौन हैं महिलाएं

न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला की उम्र 22 साल जबकि दूसरी की 40 साल है।

अंधेरे में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से शुरुआत में इनमें अंधेपन के लक्षण देखे गए। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद इन्होंने सावधानी नहीं बरती जिसके चलते अब ये पूरी तरह आंखों की रौशनी गंवा चुकीं हैं। इस बीमारी का नाम ट्रांजिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस बताया जा रहा है।

एक आंख का न करें इस्तेमाल

रिपोर्ट के मुताबिक अंधेरे में फोन इस्तेमाल करते हुए आंख स्क्रीन की रोशनी के हिसाब से काम कर रही होती है लेकिन जैसे ही आप दूसरी आंख का इस्तेमाल करते हैं दोनों तारतम्य नहीं बैठा पाते और ब्लाइंडनेस का अनुभव होता है। इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है।

आजकल स्मार्टफोन का हर जगह हर समय इस्तेमाल करना लोगों की आदत हो गई है, लेकिन अगर आप भी अपना स्मार्टफोन बाथरूम में लेकर जाते है तो संभल जाएं क्योंकि इसका बाथरूम में इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। बाथरूम में फोन को लेकर जाने से उसके गिरने या स्क्रीन के डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि गीले हाथों से स्मार्टफोन का प्रयोग करने से टचस्क्रीन खराब होती है। बाथरूम में स्मार्टफोन का बार-बार इस्तेमाल करने से सिम कार्ड में भी नमी आ सकती है। बाथरूम में नमी के कारण स्मार्टफोन के सर्किट्स पर असर पड़ सकता है क्योंकि भाप या पानी की एक बूंद भी इसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बाथरूम में साबुन, पानी के साथ आप खुद को साफ कर लेते हैं लेकिन स्मार्टफोन को नहीं कर पाते नतीजतन 10 में से 9 फोंस में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु रहते हैं। बाथरूम के बड़े शीशे के सामने बैठकर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से वाई-फाई सिग्नल ब्रेक होता है क्योंकि बड़े शीशे वाई-फाई सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते है और उसके कारण सही सिग्नल आपके फोन तक नहीं पहुंच पाते। प्राप्त रिसर्च के अनुसार, यूके में प्रत्येक महीने 1.5 लाख स्मार्टफोन फ्लश में गिर जाते है। एक स्टडी के अनुसार बाथरूम में फोन का ज्यादा इस्तेमाल व्यक्ति को लंबे समय तक वही रहने की आदत डाल देता है।

बाथरूम में न ले जाएं फोन

क्या हैं लक्षण

शुरुआत में इन महिलाओं को कुछ वक्त के लिए दिखाई देना बंद हो जाता था। महिलाओं के कई टेस्ट किए गए लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता नहीं चल पाया। बाद में इन महिलाओं से जब पूछा गया कि ऐसा अक्सर कब होता है तो उन्होंने बताया कि रात में जब वे लेटकर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहीं होती हैं तब ऐसा अक्सर होता है। तो अगर आपको भी टेम्परेरी ब्लाइंडनेस का अनुभव हो रहा है तो ये संभल जाने का वक्त है।

एंटीबायोटिक लेने से पहले ध्यान रखें ये बातें

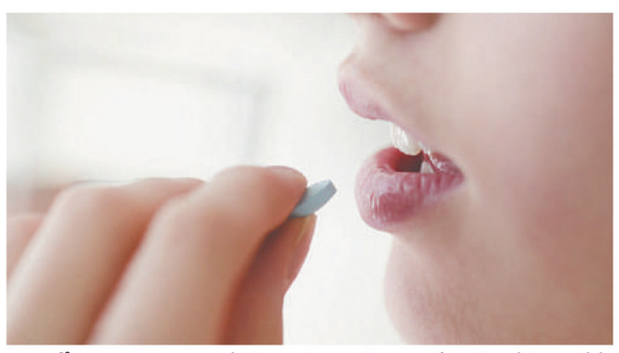

सर्दी-जुकाम या बुखार में बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स लेने की आदत सेहत के लिए कई दिक्कतें पैदा कर सकती है। ब्रिटेन में हुए एक शोध के अनुसार बार-बार एंटीबायोटिक्स लेने से पेट में मौजूद खराब बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। जिससे बैक्टीरियल सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसे में पैंक्रियाज की कार्य प्रणाली बिगड़ने के कारण टाइप-टू डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।

बार-बार एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से शरीर में इनके प्रति रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है। जिस वजह से कुछ समय बाद मौसमी बीमारियों में ली जाने वाली एंटीबायोटिक्स दवाएं न के बराबर असर करती हैं। ऐसे में मरीज हाई डोज वाली एंटीबायोटिक्स का आदी होने लगता है जो गंभीर रोगों को जन्म देती हैं।

ये हैं साइड इफेक्ट्स

इन दवाओं के लिए नियमित डोज और कोर्स होता है। सही तरीके से एंटीबायोटिक्स न लेने पर साइड इफेक्ट हो सकता है। इसमें स्टेफन जॉनसन सिंड्रोम बेहद आम है। इस सिंड्रोम में मुंह में छाले और चेहरे व छाती पर दाने निकल आते हैं। यह जानलेवा भी हो सकता है।

वायरल में असरदार नहीं

एंटीबायोटिक्स वायरल फीवर में अधिकतर मरीज बिना किसी डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। जो असर नहीं दिखाती है। एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया मरते हैं जबकि वायरल फीवर वायरस के कारण होता है। ऐसे में एंटीबायोटिक्स खाने से शरीर को नुकसान होता है।

5-7 दिन में ठीक होता है वायरल

वायरल फीवर, सर्दी-जुखाम होने पर एक निश्चित समय के बाद ही ठीक होता है। इसमें 5-7 दिन लगते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स दवाएं नहीं लेनी चाहिए। केवल फीवर या सर्दी की दवा लें। निर्धारित समय में अपने से ठीक हो जाएगा। डायरिया-दस्त में या बाहर खाना खाने के बाद भी एंटीबायोटिक्स न खाएं। इसे लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

6 बागी सांसद शिवसेना में शामिल

मुंबई। महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासी जंग के बीच उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना (यूबीटी) के 6 बागी सांसद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं. शिंदे कैंप में शामिल होने वाले सांसदों में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, पाटिल-अष्टिकर और ओमप्रकाश राजेनिंबालकर का नाम शामिल है.इन सांसदों ने 17 जून को दिल्ली में हुई शिवसेना (यूबीटी) पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था. इसके बाद से ही उनके पार्टी बदलने की अटकलें तेज हो गई थीं. सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान खुद एकनाथ शिंदे ने किया. इस मौके पर उन्होंने कहा, अब मेरे पास तीन संजय हैं.साथ ही उन्होंने 2022 की बगावत को याद किया.उस समय 40 विधायकों ने बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया था. उन्होंने कहा कि हम हमेशा बालासाहेब ठाकरे की आइडियोलॉजी को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. ये बगावत का दूसरा चरण हैं।

भरत एनकाउंटर केस में रुख का तत्काल सुनवाई से इनकार

पटना। बिहार के भोजपुर जिले में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है. बीते दिन इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की विशेष मांग की गई थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई की अपील करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को तय प्रक्रिया का पालन करने को कहा है. अदालत ने निर्देश दिया है कि जल्द सुनवाई के अनुरोध के लिए वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से संपर्क करें. अब रजिस्ट्री से अनुमति मिलने के बाद ही साफ होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कब सुनवाई करेगा. बता दें कि भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले की सुनवाई के लिए दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि भरत की मौत के इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

भारतीय के हाथ वॉट्सऐप की कमान

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप का सीईओ भारतीय होगा. वॉट्सऐप के मौजूदा सीईओ अब की जगह क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह लेंगे. मेटा इन्हें वॉट्सऐप का ग्लोबल सीईओ बना रही है. दिलचस्प ये है कि वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी मेटा कुणाल शाह की कंपनी क्रेड में लगभग 1 बिलियन डॉलर्स निवेश किया है. ये भारतीय रुपये में 900 करोड़ रुपये होते हैं. सीआरईडी एक फिनटेक ऐप है और इसे शुरुआत में कंपनी ने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट सल्यूशन के तौर पर पेश किया था. धीरे धीरे इस ऐप में कई सर्विसेज जुड़ीं और अब इस ऐप के जरिए पेमेंट से लेकर लोन तक मिल सकता है. कंपनी के प्रोडक्ट हेड क्रिस कॉक्स ने एक नोट में लिखा है. आप पूरा नोट पढ़ सकते हैं. कुछ जरूरी जानकारी शेयर करनी है. सात साल तक वॉट्सऐप को लीड करने के बाद विल कैथकार्ट ने फैसला किया।

मुस्लिम सीएम चेहरा घोषित करें अखिलेश, हमारा अहसान चुकाएं

लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से एक बड़ी मांग की है. जमात ने बकायदा एक पत्र लिखकर अखिलेश यादव से अपील की है कि वह उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें. न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पत्र में साफ कहा गया है कि अखिलेश यादव के पूरे परिवार पर मुसलमानों का बहुत बड़ा अहसान है. इसलिए वक्त आ गया है कि अब वह इस अहसान को चुकाएं, साथ ही अपनी पार्टी के ही किसी मुस्लिम चेहरे को आगे करके साल 2027 का चुनाव लड़ें. जमात की तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 22 प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि यादव बिरादरी के लोग सिर्फ 7 प्रतिशत के करीब हैं. ऐसे में समाजवादी पार्टी के भीतर सबसे बड़ी हिस्सेदारी और पार्टनरशिप मुसलमानों की ही बनती है।

नीतीश का ताज निशांत की ओर शिफ्ट हो रहा?

पटना। बिहार की सत्ता से हटने के बाद नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को सियासी पिच पर उतारा. सम्राट चौधरी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवाकर निशांत को राजनीति में लांच किया, लेकिन अब नीतीश कुमार का सियासी ताज धीरे-धीरे निशांत कुमार की ओर शिफ्ट होने लगा है. जेडीयू के नेताओं को भी पार्टी का भविष्य निशांत कुमार में दिखने लगा है. जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद बैठक में रविवार को नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश के बाद कौन का सवाल उठा तो जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं की जुबान पर सिर्फ निशांत कुमार का नाम ही गूंजा.नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी देते हुए संजय झा ने कहा कि कहा कि पार्टी अब नए चरण में आगे बढ़ रही है. बैठक में जेडीयू के भावी सियासत को लेकर भी लकीर खींचा गया, जिसमें पार्टी नेताओं से लेकर मंत्री और विधायक तक को जेडीयू का सियासी भविष्य निशांत कुमार में दिख रहा है. मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीतिक में नहीं लाए थे, लेकिन सत्ता छोड़ते ही उन्होंने निशांत कुमार के सियासी पिच पर उतारा, और सम्राट सरकार में स्वस्थ्य मंत्री बनवाने का काम किया।

युवा आईएएस अधिकारियों से पीएम मोदी का संवाद, दिया गुरुमंत्र

फाइलों में अनगिनत नागरिकों की आकांक्षा-जिंदगियां

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2024 बैच के 183 आईएएस प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। ये सभी अधिकारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में तैनात हैं। इस दौरान युवा अधिकारियों ने अपने फील्ड प्रशिक्षण और मंत्रालयों के कामकाज के अनुभव साझा किए।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दो साल के जमीनी अनुभव के बाद वे अब एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां उनके फैसले करोड़ों नागरिकों का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि लोक सेवा की असली परीक्षा ईमानदारी, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ वास्तविक स्थितियों को संभालने में है।

प्रधानमंत्री ने युवा सिविल सेवकों से राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित रहने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिक देवो भव का मंत्र देते हुए कहा कि हर प्रशासनिक फाइल के पीछे एक इंसान की उम्मीदें, चिंताएं और जीवन छिपा होता है। अधिकारियों को हर फैसला लेते समय नागरिकों को केंद्र में रखना चाहिए। उन्होंने शासन को अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी बनाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने होल-ऑफ-गवर्नमेंट यानी पूरे सरकारी तंत्र के एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि बड़ी विकास चुनौतियों को अलग-अलग रहकर हल नहीं किया जा सकता। विभागों के बीच बेहतर तालमेल ही सार्थक और स्थायी परिणाम ला सकता है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक फैसला देश के विकास में योगदान देने वाला होना चाहिए। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा सुरक्षा और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने को आज की प्राथमिकता बताया।

पिछले दशक में आए बदलावों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब प्रशासन प्रक्रिया के बजाय परिणामों पर ध्यान देता है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक से सेवाओं में पारदर्शिता आई है और नागरिकों का काम आसान हुआ है।

डेटा-आधारित शासन पर बात करते हुए पीएम ने कहा कि डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह लाखों लोगों की चुनौतियों और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नियमित रूप से जांचें कि क्या नीतियां जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बैच में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बताया कि इस बैच में 40 प्रतिशत से अधिक महिला अधिकारी हैं। अंत में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने पद से नहीं, बल्कि अपने काम से मिलने वाले परिणामों से संतुष्ट हों। उन्हें पूरा भरोसा है कि इन युवाओं की ऊर्जा भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

छह सांसदों के पार्टी छोड़ने पर शिवसेना यूबीटी ने उठाए सवाल

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) ने मंगलवार को सत्ताधारी महायुति गठबंधन पर तीखा हमला किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर महाराष्ट्र के 25 साल पीछे धकेलने और राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया। शिवसेना (यूबीटी) ने आरोप लगाया कि शिंदे की अहंकारी पैसे वाली राजनीति का तरीका आखिरकार फडणवीस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। उनका दावा है कि दिल्ली में भाजपा नेतृत्व का एक गुट खुलेआम शिंदे को मुख्यमंत्री के अधिकार को चुनौती देने के लिए बढ़ावा दे रहा है।

ठाकरे गुट ने पार्टी के मुखपत्र सामना में महायुति सरकार पर धोखे का जश्न मनाने का आरोप लगाया। उन्होंने ऑपरेशन टाइगर का जिक्र किया, जिसमें सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। संपादकीय में कहा गया, महाराष्ट्र को परेशान करने वाले गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के पाला बदलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि धोखे का ऑपरेशन सफल रहा और मरीज ठीक है। संपादकीय में कहा गया है कि ऐसे समय में जब महाराष्ट्र कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। फडणवीस का गद्दारों की तारीफ करके संतुष्टि पाना गलत है। इसके साथ ही संपादकीय में अफसोस जताया गया कि जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही गद्दारों के दिलों में डर पैदा हो जाता था। वहीं मौजूदा नेतृत्व सक्रिय रूप से राजनीतिक दल-बदल का जश्न मना रहा है और धोखे को महाराष्ट्र की नई पहचान बना रहा है। ठाकरे गुट ने पूरे राज्य में प्रशासनिक लापरवाही की कड़ी आलोचना की। इसमें कहा गया, बारिश में देरी के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र पर पानी की भारी किल्लत का संकट मंडरा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन और मवेशियों के लिए चारे की कमी का खतरा पैदा हो गया है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात बांधों में पानी का स्तर गिरकर खतरनाक रूप से 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे तुरंत पानी की कटौती करनी पड़ रही है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तमिलनाडु सीएम विजय ने विपक्ष पर साधा निशाना

डीएमके के सदस्यों ने सदन से किया वॉकआउट

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मंगलवार को विपक्षी डीएमके पर तीखा हमला किया। उन्होंने अपने पूर्व शासनकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार को पार्टी फंड करार दिया। डीएमके सदस्य ने विधानसभा के अंदर इस बयान का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वॉकआउट कर गए। विपक्षी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने उस समय कड़ा विरोध दर्ज कराया जब मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की कि पिछली डीएमके सरकार ने अगलड़ा अलग सरकारी विभागों के फंड को पार्टी फंड की ओर डायवर्ट किया था।

सदन में विजय के जवाब को रोकने की कोशिश करते हुए उदयनिधि खड़े हुए और अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर से आग्रह किया कि वे मुख्यमंत्री को डीएमके के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करने के लिए राजी करें। हालांकि, अध्यक्ष ने विजय के भाषण के दौरान किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया और कहा कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल के विधानसभा अभिभाषण का जवाब पूरा करने दिया जाना चाहिए। लेकिन डीएमके सदस्य विरोध में खड़े रहे। अपने भाषण को फिर से शुरू करते हुए विजय ने कहा कि पिछली डीएमके सरकार के विपरीत, टीवीके कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी और न ही किसी को सरकारी खजाने को लूटने की अनुमति देगी।

शोरगुल भरे विरोध प्रदर्शनों के बीच, मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी कड़ा रुख अपनाते हुए पिछली सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पार्टी फंड संग्रह की आड़ में कथित रूप से गबन किए गए सार्वजनिक धन की वसूली करेगी। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को, चाहे वह डीएमके सरकार के दौरान ही क्यों न हुआ हो, कानून के कटघरे में लाया जाए। उनकी तीखी टिप्पणियों पर विपक्ष की ओर से तत्काल और जोरदार आपत्ति जताई गई। उदयनिधि ने विरोध जताते हुए अध्यक्ष से सदन में जवाब देने की अनुमति देने की मांग की।

डीएमके के इस दावे को खारिज करते हुए कि सत्तारूढ़ टीवीके उसकी दया के कारण सत्ता में बनी रही, विजय ने कहा कि वामपंथी दलों ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया। वहीं, कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल, जिन्होंने समर्थन दिया, उन्हें नए मंत्रिमंडल में समायोजित किया गया। विजय ने कहा, %हम डीएमके की दया पर निर्भर नहीं हैं। हम जनता की कृपा से सरकार चला रहे हैं, जिन्होंने हमें चुना है।% यह कहते ही मुख्यमंत्री का भाषण पूरा होने से पहले ही उदयनिधि के नेतृत्व में डीएमके सदस्य सदन से बाहर चले गए।

विपक्ष के वॉकआउट से अविचलित विजय ने अपनी सरकार की स्थिरता और जनादेश का बचाव किया और विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया कि उनका प्रशासन पूरी तरह से बाहरी राजनीतिक ताकतों की दया या समर्थन पर चलता है। विजय ने कहा, %डॉ. अंबेडकर का सौ साल पुराना सपना अब पूरा हो गया है। मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य मेरी बात सुनें। विपक्ष में जो लोग खुद को महिलाओं का रक्षक बताते हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट में कितनी महिलाओं को शामिल किया। हमारी कैबिनेट में चार महिलाओं को मंत्री पद दिया है। जिन्हें जनता ने नकार दिया है, उनसे हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं।

विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उदयनिधि ने कार्यवाही की निंदा की और सदन के अंदर कथित प्रक्रियात्मक उल्लंघनों पर सवाल उठाए। विपक्ष के प्रतिनिधि ने कहा, अगर मुख्यमंत्री के पास कदाचार के ठोस सबूत हैं, तो उन्हें निराधार आरोप लगाने के बजाय उन्हें औपचारिक रूप से सदन में पेश करना चाहिए।%

खेल
प्रमुख समाचार

नीतीश रेड्डी आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर

नईदिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे से पहले बड़ा झटका लगा है। युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी क्वाड्रिसेप्स (जांघ की मांसपेशी) में चोट के कारण आयरलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में सूजन और मांसपेशियों में चोट (फाइबर डिसरप्शन) पाई गई है, जिसके बाद उन्हें आगे की जांच और उपचार के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने को कहा गया है।

नीतीश को हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान यह चोट लगी थी। शुरुआती आकलन में चोट ज्यादा गंभीर नहीं लग रही थी, लेकिन एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद स्थिति चिंताजनक पाई गई। माना जा रहा है कि उनकी रिकवरी में कम से कम चार सप्ताह का समय लगेगा, जबकि रिहैब में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है।

नीतीश रेड्डी को इस दौरे पर खास जिम्मेदारी मिलने वाली थी। वह हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में टीम के प्रमुख तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले थे। हार्दिक भी क्वाड्रिसेप्स की समस्या से जूझ रहे हैं और फिलहाल वनडे क्रिकेट में लगातार 10 ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में नीतीश का बाहर होना टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलन प्रदान करते हैं।

23 वर्षीय नीतीश अब तक भारत के लिए 10 टेस्ट, छह वनडे और चार टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में उन्होंने दो मैच खेले थे, जबकि लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे से वह बाहर रहे थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 893 अंक लुढ़का निफ्टी 23,824 पर बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को बिकवाली का दबाव देखने को मिला। धातु, आईटी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट के चलते प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भी भारतीय बाजार पर साफ नजर आया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 893.39 अंक यानी 1.16 फीसदी टूटकर 76,200.68 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई का निफ्टी 50 सूचकांक 278.80 अंक यानी 1.16 फीसदी की गिरावट के साथ 23,824.10 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में इंफोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के शेयर सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में शामिल रहे। निवेशकों की बिकवाली के चलते इन शेयरों पर दबाव बना रहा। मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ व्यापक बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली।

आरबीआई ने 57 साल पुरानी लीड बैंक योजना में किए बदलाव

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 जून से 57 साल पुराने लीड बैंक योजना में कई बदलाव किए हैं। केंद्रीय बैंक का कहना है कि बदलती अर्थव्यवस्था, डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दायरे और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना को आधुनिक बनाने की आवश्यकता थी। नई गाइडलाइंस का उद्देश्य छोटे कारोबारियों, किसानों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग सेवाओं और वित्तीय सहायता को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। लीड बैंक योजना की शुरुआत साल 1969 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक जिले में प्रमुख बैंक को जिम्मेदारी दी जाती है कि वह बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करे और लोगों तक लोन और दूसरी वित्तीय सुविधाएं पहुंच सकें। अब आरबीआई ने इसी पुराने सिस्टम को नए दौर के हिसाब से अपडेट किया है।

भारती एयरटेल ने एयरटेल अफ्रीका में हिस्सेदारी बढ़ाई

नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने शेयर अदला-बदली समझौते के जरिये एयरटेल अफ्रीका में अपनी हिस्सेदारी 16.31 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 79 प्रतिशत कर ली है। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि इस सौदे का मूल्य करीब 28,200 करोड़ रुपए आंका गया है। इस लेनदेन से पहले भारती एयरटेल की एयरटेल अफ्रीका में हिस्सेदारी 62.73 प्रतिशत थी। कंपनी सूचना के अनुसार, कंपनी ने 22 जून 2026 को आईसीआईएल से एयरटेल अफ्रीका के 595,204,251 शेयर (करीब 16.3 प्रतिशत हिस्सेदारी) का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी की प्रभावी हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 79 प्रतिशत हो गई है। इस लेनदेन के तहत भारती एयरटेल ने अपने प्रवर्तक समूह की इकाई इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को तरजीही आधार पर शेयर जारी किए।

एलन मस्क की कंपनी का 3 दिन में 600 अरब डॉलर डूबे

वाशिंगटन। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में पिछले तीन दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयरों में आई बड़ी बिकवाली से उसकी मार्केट वैल्यू में 600 अरब डॉलर (लगभग 55 लाख करोड़) से अधिक की कमी दर्ज की गई है। सोमवार को कंपनी के शेयर 16.4% तक क्रैश हो गए और इसकी क्लोजिंग 154.60 डॉलर पर हुई, जो लिस्टिंग के बाद का सबसे निचला स्तर है। पिछले तीन कारोबारी सत्रों में शेयर करीब 23 फीसदी गिर चुके हैं। इसके बावजूद कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 2 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक बना हुआ है। स्पेसएक्स की वैल्यूएशन में 600 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट की तुलना कई अर्थशास्त्री यूएई की कुल जीडीपी से बराबर कर रहे हैं।

देश में गहरे आर्थिक सुधारों की जरूरत, बढ़ती असमानता और वैश्विक संकट

रामचंद्र गुहा

पिछले एक साल में यह स्पष्ट हो गया है कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। रुपया कमजोर पड़ता गया, विदेशी निवेश वापस लौट रहा है और घरेलू निजी निवेश सुस्त है। उपभोग की मांग कमजोर बनी हुई है, विनिर्माण क्षेत्र में ठहराव आ चुका है और अमीर तथा सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से पैदा हुई चुनौतियों के कारण प्रमुख आईटी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। शेयर बाजार का माहौल इन तमाम समस्याओं को प्रतिबिंबित कर रहा था और प्रमुख सूचकांक लगभग वहीं खड़े थे, जहां वह दो वर्ष पहले थे।

इन सब चुनौतियों की समझ ने पेशेवर अर्थशास्त्रियों को लगातार लेख लिखने के लिए प्रेरित किया है, जिनमें वे मोदी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह समस्याओं की गंभीरता को स्वीकार करें और आवश्यक सुधारों की शुरुआत करें। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ऐसे लेखों की संख्या और बढ़ गई है। इस संघर्ष ने तेल, गैस, उर्वरक तथा अन्य वस्तुओं के वैश्विक बाजारों में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे भारत का व्यापार संतुलन प्रभावित हुआ है और कई क्षेत्रों में कमी की स्थिति बनी है। युद्ध के कारण विदेशों से आने वाली धनराशि (रेमिटेंस) भी घटी है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है।

अर्थशास्त्रियों द्वारा सुझाए गए सुधारों में सीमा शुल्क, कर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली को कम मनमाना और कम प्रतिशोधात्मक बनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, श्रम-प्रधान विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, निवेशकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना ताकि केवल कुछ चुनिंदा उद्योगपति ही लाभकारी परियोजनाओं पर कब्जा न कर सकें। उर्वरक और बिजली सब्सिडी को कम करना, भाजपा-शासित और गैर-भाजपा-शासित राज्यों के बीच भेदभाव समाप्त करना तथा आर्थिक मंत्रालयों में कार्यरत कमजोर प्रदर्शन करने वाले नेताओं और नौकरशाहों के स्थान पर अधिक सक्षम और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना शामिल है।

देश के प्रमुख नीति-अर्थशास्त्रियों के सुझावों का उद्देश्य जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र या राजनीतिक विचारधारा से परे सभी भारतीयों के कल्याण और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इन सुझावों में मैं अपना एक और प्रस्ताव जोड़ना चाहूंगा- हमारी हवा, पानी, मिट्टी और वनों के लगातार हो रहे क्षरण को रोकने की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या केंद्र सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करेगी और उन पर गंभीरता से अमल करेगी? मेरा मानना है कि यदि हम उन दो व्यक्तियों की प्राथमिकताओं पर नजर डालें, तो जो इस सरकार में सबसे अधिक प्रभाव रखते हैं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह-तो इसका उत्तर संभवतः 'न' होगा।

मुझे प्रधानमंत्री तीन प्रमुख महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित लगते हैं। पहली महत्वाकांक्षा है किसी भी कीमत पर और जितना संभव हो सके, सत्ता में बने रहना। वे स्वयं उस 75 वर्ष की आयु सीमा को पार कर चुके हैं, जिसे उन्होंने कभी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 'मार्गदर्शक मंडल' में भेजने के लिए एक मानदंड के रूप में स्थापित किया था। इसके बावजूद, उम्र बढ़ने और ऊर्जा में स्वाभाविक कमी आने के बाद भी, सत्ता छोड़ने के कोई संकेत दिखाई नहीं देते। वे लगातार चौथी बार लोकसभा चुनाव जीतने की आकांक्षा रखते हैं, जिससे वे जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकें।

दूसरी महत्वाकांक्षा अपने व्यक्तित्व के इर्द-गिर्द बने महिमामंडन को और अधिक मजबूत करना है। पेट्रोल पंपों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले अनेक सार्वजनिक स्थलों पर उनकी तस्वीरों की व्यापक मौजूदगी इसका उदाहरण है। तीसरी महत्वाकांक्षा एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है, चाहे वह व्यावहारिक रूप में हो या संवैधानिक रूप में। वर्ष 2014 में उन्होंने 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा दिया था, लेकिन मेरा मानना है कि बाद में वे उस आदर्श से दूर हो गए। अब वे खुद को हिंदू समाज के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

खेलों के लिए बेहतर अधोसंरचना का हो रहा विकास: साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर नवा रायपुर के ग्राम पलोद में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित वृक्षारोपण एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह में शामिल होकर रुद्राक्ष का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए खेल और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्र निर्माण के दो महत्वपूर्ण आधार बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत ने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा प्रस्तुत किया है। इसी राष्ट्रीय संकल्प और आकांक्षा को प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए कार्यक्रम में 2036 पौधों का रोपण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल वृक्षारोपण अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ, हरित और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य में खेलों के लिए बेहतर वातावरण और आधुनिक अधोसंरचना विकसित की जा रही है ताकि युवा अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स की सफल मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है। वहीं बस्तर ओलंपिक जैसे अभिनव आयोजन ने दूरस्थ अंचलों की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दी है। इस वर्ष बस्तर ओलंपिक में लाखों युवाओं ने भाग लेकर अपनी क्षमता का परिचय दिया है, जो प्रदेश में खेलों के प्रति बढ़ते उत्साह का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल क्षेत्र में विशेष बजट प्रावधान कर रही है। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानजनक प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों तथा वन विभाग के खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में खेलो इंडिया जैसी योजनाओं ने देश में खेल संस्कृति को नई पहचान दी है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश के युवाओं में अपार प्रतिभा है और सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन भी युवाओं को नई दिशा प्रदान कर रहा है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. विक्रम सिंह सिसोदिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय, बीएसएफ के आईजी संजय पंत सहित अनेक जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

अटल नगर नया रायपुर में 25 जून को टेक्सटाइल पार्क का होगा शुभारंभ

■ सीएम विष्णुदेव साय करेंगे उद्घाटन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नई उद्योग नीति के तहत नया रायपुर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 25 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इसकी जानकारी उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित सहयोग केंद्र में दी।

मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार नए उद्योग प्रारंभ हो रहे हैं। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उद्योग यहां स्थापित हों और छत्तीसगढ़ के नौजवान, पढ़े-लिखे मजदूर भाइयों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो। इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है।

बुधवार को भाजपा के सहयोग केंद्र में उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगनने कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान सहयोग केंद्र में करीब 60 से 70 आवेदन प्राप्त हुए। मंत्री ने समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मौके पर ही सुनवाई की गई।

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज सहयोग केंद्र था, जिसमें लगभग 60 से 70 भाजपा कार्यकर्ता और अन्य लोग अपनी छोटी-बड़ी समस्याएं लेकर आए थे। उनके निराकरण का प्रयास किया गया है। कई आवेदन ऐसे भी होते हैं, जो संबंधित विभाग से जुड़े नहीं रहते। ऐसे आवेदनों को हम संबंधित विभाग में भेजते हैं और आने वाले समय में उनका भी निराकरण होगा। अलग-अलग दिनों में अलग-अलग सहयोग केंद्र आयोजित होते हैं। इसी क्रम में आज मैं सहयोग केंद्र में बैठा हूं और आम जनता की समस्याओं का निराकरण किया है।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर : मुख्यमंत्री साय

रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में प्रख्यात शिक्षाविद्,भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, राष्ट्रवादी चिंतक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के सशक्त प्रहरी थे। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया। उनके विचार, संघर्ष और त्याग भारतीय लोकतंत्र एवं राष्ट्रवादी चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र की अखंडता और सांस्कृतिक अस्मिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते समय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर ही हम राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, श्री राम गर्ग सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की तैयारियों की अधिकारियों से ली जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान शीघ्र ही प्रारंभ होगा। अभियान के तहत शासन की 31 जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा प्रत्येक पात्र परिवारों को पहुंचाया जाएगा। यह अभियान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और सरगुजा संभाग के 23 जिलों में प्रारंभ किया जाएगा। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में इस संबंध में अधिकारियों से की जा रही व्यापक तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। उल्लेखनीय है सुघ्घर छत्तीसगढ़ योजना छत्तीसगढ़ शासन कीई पहल है। जिससे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का फायदा सभी पात्र परिवारों को दिया जाएगा। योजना के फायदें से कोई वंचित न रहें इसके लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। सुघ्घर छत्तीसगढ़ के तहत अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के जरिये विस्तार से जानकारी दी। बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

कौन से गांव में कितना भू-जल, एनआईटी रायपुर करेगा वैज्ञानिक अध्ययन

रायपुर। जिले में भू-जल स्तर के संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर संचालित मोर गाँव मोर पानी अभियान को और अधिक प्रभावी एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। जिले के विकासखंड धमतरी एवं कुरूद को भू-जल दोहन की स्थिति के आधार पर क्रमशः क्रिटिकल एवं सेमी-क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण के स्थायी समाधान विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), रायपुर के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तावित किया गया है।

इस अध्ययन के तहत एनआईटी रायपुर की विशेषज्ञ टीम चयनित ग्रामों में उपलब्ध भू-जल की स्थिति, जल स्त्रोतों की क्षमता, जल स्तर में हो रहे बदलाव तथा वर्षा जल के संरक्षण की संभावनाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करेगी। अध्ययन में यह भी आकलन किया जाएगा कि किस गांव में कितना भू-जल उपलब्ध है, जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा किन उपायों से भू-जल स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे एवं स्पॉट स्टडी के आधार पर जल संरक्षण एवं भू-जल पुनर्भरण के लिए सबसे उपयुक्त संरचनाओं की पहचान की जाएगी।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा द्वारा राज्य स्तर पर प्रेषित प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि एनआईटी रायपुर के विशेषज्ञ चयनित ग्रामों एवं स्थलों का स्पॉट स्टडी तथा हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वे कर भू-जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त संरचनाओं की पहचान करें। साथ ही उनके तकनीकी डिजाइन, संभावित प्रभाव, जल पुनर्भरण क्षमता तथा क्रियान्वयन की कार्ययोजना संबंधी विस्तृत तकनीकी प्रतिवेदन तैयार किया जाए।इस संबंध में एनआईटी रायपुर के सहायक प्राध्यापक डॉ. विकास कुमार विद्यार्थी ने अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रभावी अनुशंसाओं एवं दीर्घकालिक परिणामों के लिए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होगा। उन्होंने अध्ययन कार्य हेतु प्रस्तावित ग्रामों एवं स्थलों की संख्या तथा उनका विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि संस्थान द्वारा विस्तृत कार्ययोजना, तकनीकी प्रस्ताव तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान का आकलन तैयार किया जा सकेगा ।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आपातकाल संवैधानिक प्रावधान था: दीपक बैज

रायपुर। आपातकाल पर भाजपा भ्रम फैला रही है। देश में आपातकाल तो अब लागू है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आपातकाल लगाना देश की परिस्थितियों के अनुरूप महामहिम राष्ट्रपति और तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था। देश की परिस्थितियां उस समय नियंत्रण के बाहर थी। देश में कानून व्यवस्था, लॉएन आर्डर, और तमाम तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये, सुदृढ़ करने के लिये आपातकाल का निर्णय लिया गया था और जब स्थितिया सुधर गयी तो आपातकाल को हटा दिया गया था, उस समय जो लोग सरकार के खिलाफ विद्वेष फैला रहे थे, दंगा फैला रहे थे, उन लोगो के खिलाफ निरूद्ध करने के लिये कार्यवाही की गयी, उन्हें जेल में डाला गया था।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आपातकाल संविधान में प्रवाधान के तहत किया गया था, संविधान में आपातकाल लगाने का उल्लेख है। आज तो देश में पिछले एक दशक से अघोषित आपातकाल चल रहा है, 2014 से, देश के संवैधानिक संस्थाओं में कब्जा किया जा रहा है, विपक्षी दल है जो छोटे-छोटे उनके विधायको को तोड़-फोड़ कर खरीद लिया जाता है, सरकारे खरीद लिया जाता है, सांसदो को खरीद लिया जा रहा है।

मनरेगा में 40 प्रतिशत राज्य पर भार प्रदेश की जनता पर अत्याचार: शुक्ला

रायपुर। मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्रिमंडल के द्वारा मनरेगा के वित्तीय प्रावधान में 60-40 की मंजूरी दिये जाने का निर्णय राज्य के जनता पर अन्याय है। अभी तक मनरेगा केंद्र प्रवर्तित योजना थी, अब इसमें 40 प्रतिशत भाग राज्य को देना होगा। केंद्र सरकार की चाटुकारिता में साय सरकार ने राज्य के हितों का ख्याल नहीं रखा। राज्य के हिस्से को 40 प्रतिशत करने के केंद्र के फैसले का विरोध करने के बजाय इस राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। साथ ही इसके लिए 4000 करोड़ रू. का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है, जबकि अभी तक राज्य के मनरेगा पर 6200 करोड़ रू. खर्च होते थे, इसका मतलब है भले घोषित तौर पर दिन बढ़ा दिया लेकिन सरकार की नीयत मनरेगा के काम में कटौती की है जब बजट कम है तो ज्यादा दिन कैसे काम देंगे? जीरामजी कानून पास हुए 8 महीने हो गये, अमूमन 15 जून के बाद मनरेगा के काम बंद हो जाते है। सरकार अब निर्णय ले रही मतलब इस फैसले से 4 माह तक काम नहीं होगा, उसके बाद काम शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बड़ा प्रश्न यह है कि राज्य के वित्तीय संसाधन सीमित है।

राजधानी रायपुर क्राइम कैपिटल : वर्मा

रायपुर। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार प्रदेश की जनता को भयमुक्त वातावरण देने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 12 घंटे के भीतर तीन-तीन हत्या, लूट, चाकूबाजी, चैन स्नैचिंग की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के कुशासन में आम जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे है। एक ही दिन में राजधानी रायपुर में ट्रिपल मर्डर, खमतराई, भाठागांव और डब्लूआरएस कालोनी में लाशें मिली हैं। सरेआम चैन स्नैचिंग, चाकूबाजी, उठाईगिरी की घटनाएं इस सरकार और प्रशासन की क्षमता पर सवाल उठाता है। कमिश्नरी सिस्टम केवल ट्रैफिक नियमों का डर दिखाकर चालानी कार्यवाही और कमिशन वसूली तक ही सीमित है, आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। भाजपा की सरकार में पूरा छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया है, अपराधियों में कानून और पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा के कुशासन में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपराधी खुद ही अपने अपराध के वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं।

डॉक्टरों की पद रिक्त इसलिये न ईलाज हो रहा है न पढ़ाई: ठाकुर

रायपुर। सरकारी अस्पतलो में डॉक्टरों की रिक्त पदों पर भर्ती नही होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुये प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा भाजपा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद खराब है मरीजो का ईलाज नही हो पा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर हुए स्वास्थ्य सर्वे में छत्तीसगढ़ की स्थित बेहद खराब है। सरकारी अस्पतालों में 60 प्रतिशत से अधिक मरीजो के मौत के लिए डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टॉफ की कमी को जिम्मेदार माना है।ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल को जनता को जवाब देना चाहिये कि प्रदेश में 17 हजार से अधिक डॉक्टर पंजीकृत है फिर सरकारी अस्पतालों मेडिकल कालेजों, स्वास्थ्य अधिकारी के पद रिक्त क्यों है? सरकार उनकी भर्ती क्यो नही कर रही है? मेडिकल कालेज अस्पताल में चिकित्सा विशेषज्ञ के 1773 पद स्वीकृत है लेकिन मात्र 355 डॉक्टर की सेवा दे रहे है? चिकित्सा अधिकारी के 2296 पद स्वीकृत है और मात्र 37 डॉक्टर नियमित है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 518 पद स्वीकृत है उसमें 375 पद खाली है ऐसे में मरीजों का उपचार कैसे होगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कम संख्या से मरीजो के देखरेख ईलाज में दिक्कत है।

सरकार शराबबंदी लागू करे भले महतारी वंदन मत दे: वंदना

रायपुर। आबकारी मंत्री द्वारा शराब की कमाई से महतारी वंदन की राशि देने का बयान बेहद आपत्तिजनक है प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सरकार शराब की कमाई से महतारी वंदन की राशि मत दे महिलाओं को यह पैसा नही चाहिये। महिलाओं को अपना परिवार बर्बाद करके सरकार से 1000 नही चाहिये। सरकार महतारी वंदन की राशि भले मत दे, वह प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करे। वैसे भी महतारी वंदन में 1000 रू देकर बिजली बिल के नाम पर सरकार तीन गुना ज्यादा वसूल रही है। यह सरकार महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय सभी विवाहित महिला को 1000 रू. प्रतिमाह देने का वादा किया था। सरकार के आने के बाद भाजपा अपने वादे से पलट गयी। सभी विवाहित के स्थान पर इंकमटैक्सपेयी परिवार, सरकारी नौकरी परिवार की बंदिशे लगाकर महिलाओं को अपात्र घोषित किया। महतारी वंदन की पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं को राशि दी गयी। धीरे-धीरे हर माह सरकार ने कटौती कर दिया। आखिरी में लगभग 69 लाख महिलाओं को ही राशि मिल पाई।

रायपुर में उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला सम्पन्न

राज्य डेटा सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती

रायपुर। राज्य में डिजिटल गवर्नेंस के तेजी से बढ़ते दायरे और शासकीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के बीच नागरिकों के डेटा एवं महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से रायपुर में "Strengthening Cyber Security Frameworks for State Data" विषय पर राज्य स्तरीय विभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन तथा चिप्स द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों के 120 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और राष्ट्रीय स्तर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शामिल हुए।

सचिव अंकित आनन्द कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनन्द ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस की सफलता नागरिकों के विश्वास पर आधारित है और यह विश्वास तभी मजबूत होगा जब शासकीय डिजिटल प्रणालियां सुरक्षित, विश्वसनीय और साइबर खतरों का सामना करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सुशासन, सेवा निरंतरता और जनविश्वास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय बन चुका है। राज्य शासन का लक्ष्य केवल डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित और लचीला बनाना भी है। राज्य के लिए तैयार हो रहा व्यापक साइबर सुरक्षा रोडमैप चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मयंक अग्रवाल ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि राज्य शासन साइबर सुरक्षा को डिजिटल शासन की आधारशिला मानते हुए राज्य की डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए व्यापक और भविष्य उन्मुख रोडमैप तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप छह प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें जोखिम आधारित सुरक्षा मूल्यांकन, राज्य डेटा सेंटर एवं नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षा संचालन केंद्र, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, डेटा गवर्नेंस तथा साइबर जागरूकता एवं क्षमता निर्माण शामिल हैं।

विशेषज्ञों ने बताए राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा मानक तकनीकी सत्रों में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर विस्तृत जानकारी साझा की। पुलिस महानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएं) डॉ. ध्रुव गुप्ता ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून वर्ष 2027 से पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। गृह मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव एवं NATGRID के सलाहकार डॉ. सौरभ गुप्ता ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं पर प्रकाश डाला।

सफाई, पानी और ठप विकास कार्यों को लेकर भाजपा ने किया बीरगांव नगर निगम का घेराव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी बीरगांव मंडल, मां बंजारी मंडल, भाजपा पार्षद दल एवं नागरिकों द्वारा बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में व्याप्त अव्यवस्था, सफाई व्यवस्था की बदहाली, पेयजल समस्या एवं ठप पड़े विकास कार्यों के विरोध में नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया।

भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक सुबह 11 बजे बुधवारी बाजार में एकत्र हुए, जहां से रैली के रूप में निगम कार्यालय पहुंचकर महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा रायपुर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, भाजपा प्रदेश मंत्री जयंती पटेल, रायपुर शहर प्रभारी राजेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक नंदकुमार साहू सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।भाजपा रायपुर जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीरगांव नगर निगम में पिछले साढ़े चार वर्षों में जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदेश के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, लेकिन बीरगांव में सफाई, सड़क, नाली, बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास के साथ कांग्रेस को जिम्मेदारी दी थी, उस पर खरा उतरने में कांग्रेस महापौर पूरी तरह विफल रहे हैं। बीरगांव क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है और आने वाले चुनाव में जनता अपने मत के माध्यम से इसका जवाब देगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.